04 - युद्धः ताकत से ज्यादा रणनीति की अहमियत

05 - भारत की बीमार व्यवस्था व बाजार के हाथ में सेवाएं

A Daily News Magazine

भोपाल

मंगलवार, 7 अप्रैल, 2026

06 - भाजपा पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संगठन बना...

07 - संकट मोचन के दरबार में 13 मुस्लिम कलाकार भी लगाएंगे...

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 23, अंक 214, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

प्रसंगवश

ईरान किस रणनीति के बूते अमेरिका के सामने टिका हुआ है?

अमीर आजमी

पिछले सप्ताह प्राइम टाइम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का संबोधन ईरान के साथ युद्ध के हालात पर अपने नियंत्रण को दिखाने के मक़सद से था। लेकिन इसने एक बड़ी विरोधाभासी बात को भी उजागर कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान की सैन्य क्षमताएं, उसकी नौसेना, वायुसेना, मिसाइल कार्यक्रम और परमाणु संवर्द्धन से जुड़े बुनियादी ढांचे काफ़ी हद तक नष्ट हो चुके हैं। उन्होंने इस संघर्ष को अब अपने अंतिम चरण की ओर जाते हुए बताया। इसके बावजूद, उन्होंने अपनी इस बात के साथ ही आने वाले हफ़्तों में संघर्ष के और अधिक बढ़ने की धमकियां भी दीं।

इसका नतीजा यह हुआ कि असल में उनके संदेश में क्या था, ये पता नहीं लग पाया। ईरान पर जीत की घोषणा तो कर दी गई, लेकिन वह अभी तक हासिल नहीं हुई है। उनकी इस चेतावनी से बयानबाज़ी और तेज़ हो गई कि ईरान पर बमबारी करके उसे 'स्टोन एज (पाषाणकाल) में वापस ले जाएंगे।' इस बात का ईरान के अंदर सोशल मीडिया पर गुस्सा भड़क गया है। यह ईरान में ट्रंप के उन समर्थकों में भी दिख रहा है जो उन्हें शासन में बदलाव लाने वाले एजेंट के तौर पर देखते थे।

ट्रंप ने इस दावे पर भी ज़ोर दिया है कि ईरान में 'सत्ता परिवर्तन' असल में हो चुका है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई के साथ ही कई अन्य शीर्ष अधिकारियों और कमांडरों की हत्या के बाद यह बदलाव आ गया है। इससे ईरान में एक ऐसा नेतृत्व उभरा है जिसे ट्रंप ने 'कम कट्टर और कहीं ज़्यादा समझदार' बताया है।

हालाँकि ट्रंप की इस बात के समर्थन में बहुत कम सबूत हैं। तेहरान में सत्ता की संरचना में कोई बदलाव नहीं आया है। सत्ता का केंद्र अभी भी सुप्रीम लीडर का कार्यालय ही है। हालाँकि मौजूदा हालात में, उनका सीधा नियंत्रण कितना है, यह साफ़ नहीं है। लेकिन देश में न तो कोई संस्थागत टूट हुई है और न ही कोई वैचारिक बदलाव आया है। मसूद पेज़ेश्कियान अभी भी राष्ट्रपति हैं। मोहम्मद बग़र ग़ालिबाफ़ अभी भी संसद का नेतृत्व कर रहे हैं। अब्बास अराग़ची अभी भी विदेश नीति को आकार दे रहे हैं। हमलों में मारे गए कमांडरों और कई अधिकारियों की जगह उन्हीं वैचारिक खेमों के लोगों ने ली है, जो युद्ध के हालात में और भी ज़्यादा सख़्त हो गए हैं। यह सत्ता परिवर्तन से ज़्यादा सत्ता की मज़बूती जैसा लगता है। यह मज़बूती कोई इत्तेफ़ाक नहीं है।

युद्ध में ईरान का लक्ष्य पारंपरिक अर्थों में जीत हासिल करना नहीं, बल्कि टिके रहना है। सालों से, तेहरान एक सीधे-सादे सिद्धांत पर काम करता रहा है कि एक ज़्यादा ताक़तवर फ़ौजी का ताक़त के सामने टिके रहना ही कामयाबी है। इसराइल और अमेरिका के साथ अपनी लंबी लड़ाई में ईरान ने हमेशा यही माना है कि किसी एक के साथ लड़ाई हुई, तो दूसरा भी उसमें खिंच आएगा। लड़ाई शुरू हुए एक महीना हो चुका है, लेकिन ईरान का कमांड ढांचा अभी भी काम कर रहा है, उसका सरकारी तंत्र मज़बूत है, और उसकी विरोध वाली ताक़त भले ही थोड़ी कमज़ोर हुई हो, लेकिन टूटी नहीं हैं। महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों, ख़ासकर होर्मुज़ स्ट्रेट पर, उसका दबदबा अभी भी कायम है। इसी रास्ते से दुनिया की तेल सप्लाई का लगभग पांचवां हिस्सा गुज़रता है।

अगर अमेरिका अभी पीछे हट जाता है, तो इस बात का ख़तरा है कि ईरान का सबसे अहम सबक सही साबित हो जाएगा कि 'टिके रहना ही काम आता है। अगर वह लड़ाई जारी रखता है, तो उसे लगातार बढ़ती लागत का सामना करना पड़ेगा और निर्णायक जीत का कोई स्पष्ट रास्ता भी नज़र नहीं आएगा।

ट्रंप के भाषण में यही दुविधा झलकती है. लड़ाई जारी रखते हुए भी जीत का दावा करके वह अपनी दो परस्पर विरोधी ज़रूरतों के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये है अपनी ताक़त दिखाना और साथ ही लंबी लड़ाई में फंसने से बचना। इस माहौल में ट्रंप के भाषण से ठीक पहले पेज़ेश्कियान का यह बयान कि ईरान के पास लड़ाई ख़त्म करने की 'ज़रूरी इच्छाशक्ति' है, किसी रियायत के बजाय एक सोची-समझी चाल ज़्यादा लगती है।

बुधवार को सोशल मीडिया पर अमेरिकी जनता यह अमेरिका पर राजनीतिक दबाव बढ़ाने की एक कोशिश थी, ताकि ईरान को अपनी बातचीत की शर्तों में कोई बदलाव न करना पड़े। युद्ध ख़त्म करने के लिए ईरान की सीमाएं पहले की तरह ही दिख रही हैं। जो कुछ इस प्रकार हैं, सत्ता का अस्तित्व बचाना और देश की संप्रभुता की रक्षा, भविष्य में अमेरिका और इसराइल की ओर से हमले न होने की भरोसेमंद गारंटी, प्रतिबंधों में सार्थक और ऐसी राहत जो लागू हो सके, अपनी रक्षा क्षमताओं को बनाए रखना। अब तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि ईरान इन मांगों पर कोई समझौता करने को तैयार है।

अगर ईरान की मौजूदा सत्ता युद्ध के बाद भी बनी रहती है, तो उसे इन संकटों से जूझ रहे देश को फिर से खड़ा करना होगा। लेकिन सत्ता के बने रहने का एक और भी गहरा नतीजा होगा। सालों से उसकी अपनी 'रक्षा क्षमता' अमेरिका या इसराइल के किसी बड़े हमले का गुप्त ख़तरा ही ईरान पर एक लगाम का काम करता रहा है। अगर वह सीधे टकराव के बाद भी सुरक्षित बच निकलता है, तो भविष्य में दी जाने वाली धमकियों का असर कम हो जाएगा। इस बदलाव का असर अभी से ही क्षेत्रीय समीकरणों पर दिखने लगा है। कुछ अरब देश अब कथित तौर पर ट्रंप से यह कह रहे हैं कि वे युद्ध को बीच में न छोड़ें। वरना उन्हें ज़्यादा आत्मविश्वास से भरे ईरान का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए, अमेरिका एक जानी-पहचानी, लेकिन बेहद मुश्किल दुविधा में फंसा हुआ है। अगर वह युद्ध छोड़कर चला जाता है, तो इससे ईरान के 'डटे रहने' के मॉडल को ही सही साबित होने का मौक़ा मिल जाएगा। और अगर वह युद्ध में बना रहता है, तो उसे एक ऐसे युद्ध में और भी गहराई तक उलझना पड़ सकता है, जिसका कोई स्पष्ट अंत नज़र नहीं आता। इस जंग में अब तक कोई 'नया ईरान' उभरकर सामने नहीं आया है। अगर युद्ध ख़त्म होने के बाद भी स्थिति वैसी ही बनी रहती है तो सवाल यह उठेगा कि क्या अमेरिका अपनी 'जीत के दावों' को उस ज़मीनी हक़ीक़त से जोड़ पाएगा, जिसमें उसका दुश्मन, जिसे वह बदलना चाहता था, असल में वैसा ही बना रहा।

(बीबीसी हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

शरद की सुबह

हूँ तो मगर मेरे इस होने में
एक अलगाव है दुनिया से

हूँ तो बहुत ज्यादा अपने लिए
अपनी पत्नी, बच्चों के लिए
और बहुत कम दूसरों के लिए
बहुत सारे लोगों के लिए
बिल्कुल नहीं

हूँ मगर 'हां' बहुत कम है
'नहीं' बहुत ज्यादा है
शायद नहीं हूँ अन्यों के लिए

हूँ तो अहंकार से भरा हुआ
क्रोध से लबालब
लोभ, मोह से भरपूर
प्रेम है मगर प्रकट नही होता
उनके लिए, जिन्हें प्रेम चाहिए

इस हूँ से मुक्ति चाहता हूँ
जैसे नदियों ने पाया है
पहाड़ों ने, झीलों ने पाया है

वहां कहां है 'नहीं' किसी के लिए
वहां कहां है प्रेम की कमी

वे हैं बहते हुए, लहराते हुए
हर बीज को उगने की जगह देते हुए

होना चाहता हूँ इसी तरह
कि ले जाय कोई मेरा सब कुछ
तो न बोलूं
काट ले जाय मेरी बांह
तो भी मुस्कराता रहूं
उठा ले जाय कहीं
कहीं रख दे
तो फर्क न पड़े

होना चाहता हूँ इस तरह
जैसे होऊं ही नहीं अपने लिए
हो जाऊं सबके लिए।

– सुभाष राय

बीजेपी के स्थापना दिवस पर पीएम का वीडियो मैसेज

- मोदी ने कहा- देश जानता है भाजपा हर चुनौती का सामना करने को ईमानदारी से है तैयार

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत की सबसे बड़ी राजनैतिक पार्टी बीजेपी सोमवार 6 अप्रैल 2026 को अपना 47वां स्थापना दिवस मना रही है। स्थापना दिवस को लेकर देशभर में बीजेपी कार्यालयों में कई कार्यक्रम हुए। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा, देश जानता है, हर चुनौती का सामना करने के लिए बीजेपी ईमानदारी से कोशिश कर रही है, आगे भी करेगी। पहले भी सकारात्मक नतीजे मिले हैं और आगे भी मिलेंगे। उन्होंने वीडियो मैसेज में कहा, 'अंग्रेजों के दौर के सैकड़ों काले कानूनों का अंत, लोकतंत्र के लिए नए संसद भवन का निर्माण, सामान्य समाज के गरीबों के लिए 10 फीसदी आरक्षण, कानून बनाकर तीन तलाक पर रोक, सीएए, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण। ऐसे कितने ही काम हैं, जो भाजपा के ईमानदार प्रयासों का नतीजा है। हमारा मिशन अभी भी जारी है।' उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्य नाथ ने पार्टी के झंडे के साथ सेल्फी ली। मध्य प्रदेश में आज 17 नए कार्यालयों का भूमिपूजन किया जा रहा है।

शाह ने कहा- भाजपा का मंत्र नेशनल फर्स्ट

अमित शाह ने लिखा- भाजपा का मूल मंत्र हमेशा स्पष्ट रहा है, नेशनल फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट। इसी मूल भावना के साथ भाजपा का हर कार्यकर्ता दिन-रात राष्ट्र-सेवा में समर्पित है। भाजपा ने लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने के साथ देश को तुष्टीकरण से मुक्त, सुशासन, पारदर्शिता को स्थापित करने का कार्य किया है।

खालिस्तानियों ने 100-100 डॉलर देकर जुटाई भीड़

बोले- हरियाणा-दिल्ली, बीकानेर हमारे

जालंधर (एजेंसी)। कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में खालिस्तानियों ने त्रिवेणी मंदिर के बाहर भारत के खिलाफ नारे लगाए। खालिस्तानियों के जुटने से शहर में 2 घंटे तक तनावपूर्ण माहौल रहा। हिंसक घटना को रोकने के लिए कनाडा पुलिस का भारी बल तैनात रहा। खालिस्तानियों ने नारे लगाते हुए हरियाणा-दिल्ली और

बीकानेर पर अपना हक बताया। वहीं, सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि प्रदर्शन के लिए ये खालिस्तान समर्थक भाड़े पर लाए गए थे। एक्स पर एक यूजर दर्शन महाराजा ने लिखा कि खालिस्तानी आतंकियों ने लोगों को जुटाने के लिए 100-100 डॉलर का लालच दिया। इसके चलते 40 से 50 के करीब लोगों को नारे लगाने के लिए उकसाया गया।

काउंटर टेररिस्ट ग्रुप के आधुनिकीकरण के लिए 200 करोड़ रूपए की डीपीआर तैयार

एनएसजी भारत का अभेद्य कवच, इनसे हैं हम हर हाल में सुरक्षित : मुख्यमंत्री

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि यद्यपि हमारी संस्कृति हमें सबके सुख की कामना करना सिखाती है, पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में दुनिया यह भी जान गई है कि यदि कोई हमें छेड़ेगा, तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। जो जिस भाषा में समझें, उसे उसी भाषा में समझाना जरूरी है।अतिवादी ताकतें देश के विकास में बड़ी बाधक हैं। हमें ऐसी ताकतों से पूरी मजबूती से निपटना होगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (नेशनल सिक्युरिटी गार्ड) भारत का अभेद्य सुरक्षा कवच है। एनएसजी के कारण ही हमारी आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था बेहद सुदृढ़ है। देश में बीते काल में हुई किसी भी प्रकार की अतिवादी, अप्रिय घटनाओं एवं असामान्य परिस्थितियों में एनएसजी गार्ड की पूरी मुस्तैदी से मौजूदगी ने हमें यह एहसास कराया है कि एनएसजी है तो हम हर हाल में सुरक्षित हैं। एनएसजी देश की सीमा के भीतर नागरिक सुरक्षा की पक्की गारंटी की तरह है। उन्होंने कहा कि एनएसजी के जवान अपनी जान की परवाह किए बिना राष्ट्र की रक्षा में तत्पर रहते हैं। यह बल अपनी पेशेवर क्षमता, अनुशासन और तकनीकी दक्षता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सोमवार को लाल परेड मैदान में आयोजित एनएसजी-शो में सहभागिता कर एनएसजी द्वारा मध्यप्रदेश पुलिस के जवानों के लिए आयोजित समग्र क्षमता निर्माण प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन के साझा कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने लाल परेड मैदान में आयोजित एनएसजी शो देखा और कमांडो के प्रदर्शन की सराहना की। शो के दौरान एनएसजी जवानों ने मॉक टेररिस्ट अटैक का रीयलस्टिक सीन क्रिएट कर इस तरह के अटैक्स को काउंटर कर पूरी क्षमता से निपटने के लिए एनएसजी द्वारा अपनाई जाने वाली पूरी प्रकिया एवं कार्यवाही का सजीव प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह शो पुरुषार्थ और साहस से पराक्रम की पराकाष्ठा के प्रदर्शन का परिचायक है। इस प्रशिक्षण प्रदर्शन में जवानों ने हवा में उड़ते हुए जो करतब दिखाए हैं, वे सच में अद्भुत है। एनएसजी जवान हमारी सुरक्षा व्यवस्था की धुरी हैं। जल, थल, नभ हर तरह से देश पर किसी भी तरह की चुनौतियां और कठिनाइयां आ सकती हैं, इनसे निपटने की तैयारियों के लिए यह प्रशिक्षण और पूर्वाभ्यास बेहद महत्वपूर्ण है। प्रशिक्षण कार्यक्रम सह एनएसजी शो के शुभारंभ अवसर पर पुलिस बैंड द्वारा मुख्यमंत्री डॉ. यादव का अभिनंदन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसी भी प्रकार के टेररिस्ट अटैक से निपटने के लिए हम अपने सुरक्षा बलों, एटीएस और सीटीजी को और अधिक मजबूत करेंगे। सीटीजी के आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने 200 करोड़ रुपए की डीपीआर तैयार की है। जल्द ही हम इस दिशा में आगे बढ़ने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने घोषणा की कि टेररिस्ट अटैक को पूरी दक्षता से काउंटर करने सभी जरूरी प्रशिक्षण के लिए हमारी सरकार भोपाल जिले की हुजुर तहसील के ग्राम तूमड़ा में अत्याधुनिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलेगी।

व्यक्ति केंद्रित 'आप' को राघव स्वीकार्य नहीं!

राघव चड्ढा को राजयसभा में उपनेता पद से हटाना 'आम आदमी पार्टी' के आंतरिक संकट और नेतृत्व की असुरक्षा को उजागर करता है। अरविंद केजरीवाल ने जिस स्वराज और आंतरिक लोकतंत्र का सपना दिखाकर पार्टी खड़ी की थी, वह अब धीरे-धीरे एक ऐसी व्यवस्था में बदलती जा रही है, जहां एक ही धुरी के इर्द-गिर्द पूरी राजनीति घूमती है। पुराने साथियों का साथ छूटना और नए उभरते सितारों के पर कतरना पार्टी की लंबी अवधि की सेहत के लिए घातक सिद्ध हो सकता है।

राजनीति

हेमंत पाल

लेखक 'सुबह सवेरे' के स्थानीय संपादक है।

आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा को पार्टी ने उपनेता के पद से हटा दिया गया। इसके पीछे पार्टी ने जो आधिकारिक कारण बताए हैं, वे न तो स्पष्ट है और न विश्वसनीय। कहा जा रहा है कि यह 'आंतरिक समन्वय' के लिए जरूरी था। लेकिन, राजनीतिक गलियारों में साफ है कि अरविंद केजरीवाल की नेतृत्व शैली एक बार फिर परीक्षा की घड़ी में आ गई। केजरीवाल, जो कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ क्रांति के प्रतीक थे, अब उन सहयोगियों को ही किनारे लगाने का खेल खेल रहे हैं जो पार्टी को मजबूत ऊंचाइयों तक ले जा सकते थे। राघव चड्ढा जैसे युवा, परिपक्व और वाकपटु नेता का यह अपमान 'आप' के भविष्य पर सवाल खड़े करता है। क्या यह केजरीवाल का नियंत्रण बनाए रखने का पुराना तरीका है!

'आप' का राजनीतिक सफर शुरू से ही केजरीवाल-केंद्रित रहा। 2012 में पार्टी के गठन के समय अन्ना हजारे जैसे सामाजिक आंदोलनकारियों ने इसे समर्थन दिया था। अन्ना ने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को 'आप' का आधार बनाया, लेकिन जल्द ही केजरीवाल ने खुद को केंद्र में स्थापित कर लिया। अन्ना हजारे ने तो 2012 में ही पार्टी से दूरी बना ली, क्योंकि उन्हें लगा कि केजरीवाल राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण आंदोलन के मूल सिद्धांतों से भटक रहे हैं। इसके बाद योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण जैसे संस्थापक सदस्यों की विदाई हुई। 2015 में पार्टी के राष्ट्रीय परिषद बैठक में केजरीवाल समर्थकों ने इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। योगेंद्र यादव ने खुलेआम कहा था कि 'आप' अब एक व्यक्ति-केंद्रित दल बन चुका है, जहां आंतरिक लोकतंत्र का कोई स्थान नहीं। कुमार विश्वास, जो केजरीवाल के करीबी कवि-साथी थे, वे भी 2017 तक पार्टी से अलग हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने उन्हें जानबूझकर हाशिए पर धकेल दिया। इन सभी मामलों में पैटर्न एक ही था कोई भी नेता जो केजरीवाल की छाया से बाहर निकलने की कोशिश करता, उसे या तो पद से हटाया जाता या पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता।

राघव चड्ढा का मामला इसी सिलसिले का नवीनतम अध्याय लगता है। चड्ढा 'आप' के सबसे चमकते सितारों में से एक हैं। पंजाब और दिल्ली में पार्टी की मजबूत पैरवी करने वाले, वे राज्यसभा में विपक्ष के प्रभावी प्रवक्ता बने। उनकी वाकपटुता ने विपक्षी दलों को भी प्रभावित किया। उन्होंने जनहित के जो मुद्दे उठाए, वे सोशल मीडिया और लोगों में चर्चा का विषय बने। उनकी लोकप्रियता का ग्राफ 'आप' के कद से ऊपर निकलने लगा था, जो शायद केजरीवाल को रास नहीं आया। पार्टी ने उन्हें उपनेता पद से हटाते हुए कोई ठोस कारण भी नहीं बताया। आधिकारिक बयान में केवल 'पार्टी के संगठनात्मक बदलाव' का जिक्र है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चड्ढा की बढ़ती लोकप्रियता केजरीवाल को खल रही थी। खासकर दिल्ली विधानसभा चुनावों के बाद, जहां 'आप' को झटका लगा, चड्ढा जैसे युवा चेहरे पार्टी को फिर खड़ा कर सकते थे। लेकिन, केजरीवाल की शैली ऐसी नहीं। वे किसी को खुद से आगे नहीं बढ़ने देते। संजय सिंह को नेता पद पर रखना और चड्ढा को हटाना इसी का प्रमाण है। सोशल मीडिया पर चड्ढा के समर्थक इसे 'केजरीवाल का ईर्ष्या-प्रदर्शन' बता रहे हैं। क्या चड्ढा कांग्रेस या अन्य विपक्षी दलों की ओर रुख करेंगे? संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि 'आप' में रहकर उनका भविष्य सीमित हो चुका है।

इस घटना के अपने व्यापक राजनीतिक निहितार्थ हैं। 'आप' जो कभी 'आम आदमी' की आवाज थी, अब एक केंद्रीकृत, केजरीवाल-प्रधान मशीन बन चुकी है। दिल्ली और पंजाब में सत्ता बनाए रखने के बावजूद, पार्टी का राष्ट्रीय विस्तार रुक गया है। 2024 लोकसभा चुनावों में 'आप' का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। गुजरात, हरियाणा और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में प्रयास विफल हो चुके हैं। आंतरिक कलह इसका प्रमुख कारण है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद भी पार्टी ने संगठन को मजबूत नहीं किया। उल्टे, आतिशी और मनीष सिसोदिया जैसे नेता भी केजरीवाल की छत्रछाया में ही दुबक कर रह गए। राघव चड्ढा को हटाया जाना, 'आप' के युवा नेतृत्व को कमजोर करता है। भाजपा और कांग्रेस इसे हथियार बना रही हैं। भाजपा प्रवक्ता ने ट्वीट किया कि 'आप में लोकतंत्र का अंत हो चुका है'। इससे पार्टी का विपक्षी गठबंधन पर असर पड़ सकता है। 'इंडिया' ब्लाक में 'आप' की भूमिका पहले से कमजोर थी, अब चड्ढा जैसे प्रभावी वक्ता के बिना यह और कमजोर हो जाएगी।

केजरीवाल की नेतृत्व शैली पर सवाल उठना स्वाभाविक है। राजनीति में करिश्माई नेता जरूरी हैं, लेकिन बिना आंतरिक लोकतंत्र के कोई दल लंबे समय तक नहीं टिकता। 'आप' भी उसी रास्ते पर है। केजरीवाल ने कभी संगठन निर्माण पर ध्यान नहीं दिया। वे चुनावी वादों और पीआर पर निर्भर रहे। राघव चड्ढा जैसे प्रतिभावान नेता को हटाकर उन्होंने पार्टी के भविष्य को ही खतरे में डाल दिया। मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में, जहां 'आप' विस्तार की कोशिश कर रही है, ऐसे कदम स्थानीय नेताओं को हतोत्साहित करेंगे। इंदौर-भोपाल क्षेत्र में इस पार्टी के कार्यकर्ता पहले से ही असंतुष्ट हैं। यदि चड्ढा बाहर चले जाते हैं, तो यह पलायन का संकेत बनेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि 'आप' एकल नेता पर टिकी है, बिना केजरीवाल के यह ढह जाएगी। लेकिन केजरीवाल के साथ भी यह टूट रही है।

इस संकट से उबरने के लिए 'आप' में आंतरिक सुधार जरूरी हैं। पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया, युवा नेताओं को जिम्मेदारी और केजरीवाल को अधिक विकेंद्रीकरण ये कदम आवश्यक हैं। अन्यथा, पार्टी का सफर योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास और अब शायद राघव चड्ढा के साथ समाप्त हो जाएगा। भारतीय राजनीति में 'आप' जैसा प्रयोग दुर्लभ था, इसे बचाने की जिम्मेदारी केजरीवाल पर है। लेकिन, इतिहास गवाह है कि शक्ति के लालच ने कई आंदोलनों को निगल लिया। राघव चड्ढा का मामला 'आप' के पतन का शुभ लक्षण न साबित हो, यही कामना है।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 20 °c | न्यूनतम 18°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ मंगलवार, 7 अप्रैल 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

संक्षिप्त समाचार

दिल्ली शराब घोटाला केसमें खुद पैरवी करेंगे केजरीवाल

जस्टिस स्वर्णा कांता से इस केस से हटने की मांग की, अगली सुनवाई 13 अप्रैल को

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान केजरीवाल ने इस केस की जज स्वर्णा कांता शर्मा से खुद को अलग करने की मांग की। कहा कि वे खुद दलीलें रखीं। कोर्ट में कहा, 'मैं अपना पक्ष खुद रखूंगा। अपने कानूनी अधिकारों का प्रयोग करूंगा। अभी तक मैंने किसी को भी अपना वकालतनामा नहीं दिया है। जस्टिस शर्मा ने इस अर्जी को रिकॉर्ड पर लेते हुए इसकी सुनवाई 13 अप्रैल के लिए तय की। साथ ही सीबीआई को कल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और कहा कि अन्य कोई पक्ष भी यदि ऐसी अर्जी देना चाहता है तो दे सकता है। सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें उसने केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य 22 आरोपियों को शराब घोटाले केस में बरी कर दिया था।

दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा में बड़ी चूक

बैरियर तोड़ अंदर घुसी कार, ड्राइवर की तलाश में जुटी पुलिस

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा में बड़ी चूक होने का मामला सामने आया है। आज यानी सोमवार को एक कार बैरियर तोड़ते हुए गेट नंबर 2 से अंदर घुस गई। उधर, घटना की जानकारी लगते ही दिल्ली पुलिस हरकत में आ गई है। फोरेंसिक टीम भी मौके पर जांच कर रही है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए कार की तलाश में जुट गई है।

पुलिस की जांच में पाया गया कि उत्तर प्रदेश रजिस्ट्रेशन नंबर वाली एक कार गेट नंबर 2 से बैरियर तोड़ते हुए अंदर घुस गई। कार ड्राइवर ने लोहे का गेट भी तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार, ड्राइवर दिल्ली विधानसभा के स्पीकर, विजेंद्र गुप्ता के ऑफिस की ओर बढ़ा और पोर्च के पास फूलों का गुलदस्ता रख दिया। इस घटना से सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं। अधिकारी इसे संभावित सुरक्षा उल्लंघन मान रहे हैं।

भोपाल रीड्स ने मनाया 100वाँ संस्करण

भोपाल। डिजिटल विचलनों और खण्डित एकाग्रता के इस दौर में भोपाल की एक अनोखी और शांत पहल लोगों को किताबों और एक-दूसरे से जुड़ने का नया तरीक़ा दे रही है। गंभीर पाठकों का तेजी से उभरता एक समूह, 'भोपाल रीड्स' ने इस रविवार भारत भवन में अपना ऐतिहासिक 100वाँ संस्करण मनाया। शहर की दो उत्साही युवा अरुणिमा तिवारी और अस्मि सक्सेना द्वारा संयोजित यह साप्ताहिक आयोजन एक अलग ही अनुभव प्रदान करता है। लोग एक साझा सार्वजनिक स्थान पर इकट्ठा होते हैं, न चर्चा करने के लिए, न बहस करने के लिए बल्कि बस चुपचाप साथ बैठकर पढ़ने के लिए। एक साधारण विचार के रूप में शुरू हुई यह पहल, जिसका उद्देश्य पढ़ने को सार्वजनिक, सहज और आनंददायक बनाना था आज एक गहरे अर्थपूर्ण सामुदायिक अनुभव में बदल चुकी है। 100वें सत्र ने इस यात्रा को ख़ास बना दिया जहाँ बड़ी संख्या में लोग अपनी किताबों और एक-दूसरे के प्रति अपने लगाव का जश्न मनाने के लिए एकत्रित हुए। भोपाल रीड्स की सबसे ख़ास बात यह है कि यह शहर में नए आए लोगों के लिए अपनापन और जुड़ाव का एहसास पैदा करता है। यहाँ लाई जाने वाली किताबों की विविधता, यहाँ आने वाले लोगों की विविधता को दर्शाती है। 'मदर मेरी कम्स टू मी' से लेकर 'कई चाँद थे सारे आसमान तक', 'एटॉमिक हैबिट्स' से लेकर 'रेलसोंग' और 'सीइंग लाइक ए फ़ेमिनिस्ट' तक। हर पाठक अपनी दुनिया में डूबा होता है, फिर भी एक साझा शांति के पल को जी रहा होता है। इस पहल की असली ताक़त इसके लोग हैं। सनी, निमरा, भूपिंदर, अंकुर, सचिन, यावर और कई अन्य प्रतिभागी हर हफ़्ते लौटते हैं और अपनी मौजूदगी से इस समुदाय को निरंतर आगे बढ़ाते हैं। बिना किसी प्रवेश शुल्क, बिना पंजीकरण और बिना किसी बाधा या उलझी प्रक्रिया के, भोपाल रीड्स पूरी तरह समावेशी बना हुआ है। कोई भी इसमें शामिल हो सकता है। बस एक किताब लेकर आइए और अपनी जगह बना लीजिए। अपनी सादगी में ही इसकी शक्ति निहित है।

अमेरिका के थाड, रूस के एस-500 को चकमा देने की तैयारी

● भारत खुद की सुरक्षा के लिए बना रहा इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें ● चीन के एचक्यू 19 को भी आईना दिखाएंगी भारत की मिसाइलें

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत अपनी अगली पीढ़ी की इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें विकसित कर रहा है। ये मिसाइलें मारक क्षमता और प्रभाव के मामले में अग्नि-5 से कहीं ज्यादा उन्नत हैं। इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से गुप्त रखा जा रहा है, क्योंकि इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि यह दुनिया के बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे रूस के एस-500, अमेरिका के थाड और चीन के एचक्यू-19 को चकमा दे सके। इस प्रोजेक्ट का मकसद एक ऐसी मिसाइल बनाना है, जो न सिर्फ ताकतवर हो, बल्कि अग्नि-5 से हल्की भी हो। अग्नि-5 एक परमाणु-सक्षम, मध्यम-दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलहै जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने बनाया है। उम्मीद है कि यह प्लेटफॉर्म 10 से 12 वॉरहेड ले जा सकेगा और इसकी मारक क्षमता 10,000 किलोमीटर से ज्यादा होगी। कहा जाता है कि अग्नि-5 की मारक क्षमता 5,000 से 5,500 किलोमीटर के बीच है।

नई मिसाइल का डिजाइन 2025 में पूरा

मातृभूमि की एक रिपोर्ट के अनुसार नई मिसाइल का डिजाइन 2025 में पूरा हो गया था। दावा किया गया है कि समुद्र के नीचे से लॉन्च की जाने वाली के-5 और के-6 सबमरीन-लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइलों की तकनीक का इस्तेमाल इस नई मिसाइल को विकसित करने के लिए किया जा रहा है। चूंकि के-5 मिसाइलों को सबमरीन के लॉन्च ट्यूबों में रखने के लिए डिजाइन किया गया है, इसलिए उसी तकनीक का उपयोग करने से इस नए, अभी तक अज्ञात हथियार को अधिक तेजी से और कुशलता से काम करने में मदद मिलेगी। उम्मीद है कि यह मिसाइल तीन टन तक वजन वाले वॉरहेड ले जा सकेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि अपना वजन कम करने के लिए, स्टील के पुर्जों की जगह उन्नत कंपोजिट सामग्री का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे मिसाइल का वजन 20 प्रतिशत से भी ज्यादा कम करने में मदद मिलेगी, क्योंकि मिसाइल के इंजन केसिंग और अन्य हिस्सों में इन कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करने से ईंधन की दक्षता और मारक क्षमता (रेंज) बढ़ जाएगी।

मिसाइलों को चकमा देने में सक्षम

एस-500, थाड और इसी तरह के अन्य सिस्टम को मात देने के लिए, एमएआरवीएस, रडार को चकमा देने वाले एडवांस्ड डेकॉय और रडार-सोखने वाली कोटिंग्स का इस्तेमाल अहम होगा। एमएआरवीएस एक तरह का बैलिस्टिक मिसाइल पेलोड है, जिसे पृथ्वी के वायुमंडल में दोबारा प्रवेश करने के बाद अपने उड़ान मार्ग को बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे दुश्मन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम से बचने में सक्षम बनाती है।

ईरान की 'धमकी' भारत को पड़ सकती है भारी

● कच्चा-तेल 110 डॉलर पार पहुंचा, बढ़ सकती है महंगाई ● ग्लोबल सप्लाई रोकने की धमकी का होगा व्यापक असर ● भारत के आयात बिल पर 16,000 करोड़ का बढ़ेगा बोझ

नई दिल्ली (एजेंसी)। अमेरिका और ईरान के बीच बयानबाजी बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतें फिर 110 डॉलर प्रति बैरल के पार चली गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की ईरान को नर्क बनाने धमकी देने के बाद ईरान ने ग्लोबल सप्लाई ठप करने की बात कही है। इससे आज एक बैरल ब्रेंट क्रूड की कीमत 1.71 की बढ़कर 110.74 पर पहुंच गई है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर यह तनाव इसी तरह जारी रहा, तो कच्चे तेल की कीमतें 150 प्रति बैरल पहुंच सकती हैं। इसके अलावा, अगर कच्चे तेल की कीमत में 1 की बढ़ोतरी सालभर बनी रहती है, तो भारत का सालाना आयात बिल करीब 16,000 करोड़ बढ़ जाएगा।

भारत की चिंता-महंगाई और रुपए पर सीधा असर पड़ेगा

भारत अपनी जरूरत का लगभग 90 फीसदी कच्चा तेल आयात करता है। इसलिए यह स्थिति चिंताजनक है। ईरान ने होर्मुज रूट को लगभग बंद कर दिया है। दुनिया का करीब 20 फीसदी तेल और गैस इसी रास्ते से गुजरता है। इसके बंद होने से न सिर्फ कच्चा तेल, बल्कि एल्यूमीनियम, फर्टिलाइजर और प्लास्टिक की कीमतों में भी भारी तेजी आने लगी है। कच्चा तेल : कोटक सिक्योरिटीज और नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज जैसे बड़े ब्रोकरेज हाउस ने चेतावनी दी है कि अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद रहता है, तो कच्चे तेल का भाव 110 से 150 के बीच रह सकता है।

ट्रम्प का अल्टीमेटम

मंगलवार रात 8 बजे तक का समय

ट्रम्प ने ईरान को बास्टर्ड कहते हुए होर्मुज स्ट्रेट नहीं खोलने पर बड़ा हमला करने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने होर्मुज नहीं खोला तो वो उसे नरक बना देंगे। इसके साथ ही उन्होंने ईरान में पावर प्लांट और पुलों पर हमला करने की बात कही।

ईरान का पलटवार

पूरा क्षेत्र युद्ध की आग में जल जाएगा

ट्रम्प के बयान के बाद ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका और इजराइल के हमले बढ़े तो वह ग्लोबल सप्लाई चेन को ठप कर देगा। अल जजीरा की के मुताबिक ईरान ने कहा है कि वह होर्मुज के अलावा दूसरे समुद्री रास्तों को भी निशाना बना सकता है।

फारस की खाड़ी से तिरंगा लहराते सुरक्षित निकला 'ग्रीन आशा'

● अब भारत का जग विक्रम जहाज ही फंसा, सान्वी आज पहुंचेगा!

नई दिल्ली (एजेंसी)। अमेरिका-ईरान में जारी जंग के बीच लिक्विफॉयड पेट्रोलियम गैस को लेकर आ रहा भारतीय झंडे वाला जहाज ग्रीन आशा ने रविवार को होर्मुज स्ट्रेट पार कर लिया है। यह जहाज होर्मुज में फंसा हुआ था। अब भारत का केवल जग विक्रम ही होर्मुज में फंसा हुआ है। ग्रीन आशा जहाज को अब भारतीय नौसेना के निर्देशों के मुताबिक भारत की ओर रास्ता तय करना है। इससे पहले ग्रीन सान्वी ने 3 अप्रैल को होर्मुज पार किया था। रिपोर्टों के अनुसार, ग्रीन सान्वी 46,655 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर गुजरात के भरूच जिले में 7 अप्रैल को दाहेज बंदरगाह पर पहुंचने वाला है। उसी वक्त एलपीजी कैरियर मुंबई में खड़ा है, जहां सान्वी से माल उतारा जाएगा।

वहीं, एक और पोत को 4 अप्रैल को ही चेन्नई में एन्नौर की ओर मोड़ दिया गया था। यह गतिविधियां तब और बढ़ गई थीं, जब 47,612 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर जग वसंत कोलकाता पहुंचा था। वहीं, पाइन गैस पोत 45,000 मीट्रिक टन माल लेकर न्यू मंगलौर पहुंचा था। जहाजरानी मंत्रालय के अनुसार, 16 भारतीय पोत फारस की खाड़ी में हैं, जो होर्मुज स्ट्रेट के पश्चिम में हैं।

वहीं, चार जहाज ओमान की खाड़ी में हैं इसके अलावा, एक जहाज अदन की खाड़ी में है। वहीं, 2 जहाज लाल सागर में हैं। फारस की खाड़ी में मौजूद जहाजों में से 5 जहाज मूवमेंट कर रहे हैं। वहीं, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के 5 जहाज हैं। जबकि चार अन्य जहाज भी हैं।

जग्गी हत्याकांड, 20 साल बाद अमित जोगी को उम्रकैद

हाईकोर्ट बोला- समान साक्ष्य में आरोपी से भेदभाव नहीं होगा

बिलासपुर (एजेंसी)। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित रामावतार जग्गी हत्याकांड में हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि जब सभी आरोपियों पर एक ही अपराध में शामिल होने का आरोप हो, तो किसी एक आरोपी के साथ जानबूझकर अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि जब सभी आरोपियों के खिलाफ एक जैसे सबूत हों, तो किसी एक को बरी कर देना और बाकी को उन्हीं सबूतों के आधार पर दोषी ठहराना सही नहीं है, जब तक कि उसे छोड़ने का कोई ठोस कारण न हो।

● **सुप्रीम कोर्ट में 20 को होगी सुनवाई-** सुप्रीम कोर्ट से अमित जोगी को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है, हालांकि कोर्ट ने मामले को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है और 20 अप्रैल को इसकी सुनवाई होगी। जोगी की ओर से दो आदेशों को चुनौती दी गई है पहला, जिसमें सीबीआई को अपील करने की अनुमति दी।

तमिलनाडु चुनाव में 'अन्ना' इज बैक

● बीजेपी के स्टार नेता अन्नामलाई जुटे प्रचार में, दूर हुई नाराजगी

चेन्नई (एजेंसी)। तमिलनाडु में बीजेपी नेता के. अन्नामलाई चुनाव प्रचार में जुट गए। करीब एक महीने तक खामोश रहने के बाद उन्होंने अपनी चुप्पी भी तोड़ी और बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार का वादा किया।

माना जा रहा था कि एआईएडीएमके के साथ गठबंधन के कारण बीजेपी ने अपने स्टार नेता को दरकिनार किया, इससे वह नाराज थे। बीजेपी ने एआईएडीएमके से गठबंधन से पहले प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिया था। फिर चुनावों में उन्हें टिकट भी नहीं दिया। बताया जा रहा है कि अमित शाह समेत केंद्रीय नेताओं से बातचीत के बाद अन्नामलाई की नाराजगी दूर हुई।

बता दें कि पिछले कुछ समय से अन्नामलाई की भूमिका को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं। खासकर तब जब बीजेपी की उम्मीदवार सूची में उनका नाम नहीं आया। अब इन सभी अटकलों पर उन्होंने विराम लगा दिया है।

अन्नामलाई ने 2020 में राजनीति में कदम रखा

पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे के. अन्नामलाई ने 2020 में राजनीति में कदम रखा था। उन्होंने बेहद कम समय में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में जगह बना ली। 2021 में उन्होंने एल. मुरुगन की जगह तमिलनाडु में बीजेपी अध्यक्ष का पद संभाला था। अपने तेज-तर्रार और मुखर अंदाज के चलते उन्होंने राज्य में बीजेपी को नई पहचान दिलाने की कोशिश की। डीएमके के खिलाफ उनके आक्रामक रुख ने उन्हें सुर्खियों में बनाए रखा। उनके डीएमके फाइल्स अभियान ने सत्ताधारी दल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी थीं।

बीवी, महिला मित्र व नौकरानी सब की सब करोड़पति

● बिहार का एसडीपीओ तो इंटरनेशनल इनवेस्टर निकला ● किशनगंज के एसडीपीओ रहे गौतम कुमार पर शिकंजा

पटना/किशनगंज (एजेंसी)। बिहार में किशनगंज के एसडीपीओ रहे गौतम कुमार से जुड़े कई राज खुल रहे हैं। बिहार, बंगाल, दिल्ली, हरियाणा, यूपी के अलावा नेपाल की भी प्रॉपर्टी में इनवेस्ट किया है। ईओयू ने कुछ सबूत जुटा लिए है। कुछ जुटाई जा रही है। इनकी बीवी, महिला मित्र और नौकरानी सब की सब करोड़पति है। सबके पास बंगला, जमीन-जायदाद और लग्जरी कार है। एसडीपीओ गौतम कुमार की संपत्तियों के सत्यापन के लिए ईओयू ने तीन टीमें बनाई है। इसके अलावा एडीशनल एसपी के नेतृत्व में एक टीम किशनगंज में भी कैंप कर रही है। आय से अधिक संपत्ति मामले के आरोपी किशनगंज के एसडीपीओ रहे गौतम कुमार की बेनामी संपत्तियों और निवेश को आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) खंगाल रही है। इसको लेकर ईओयू की तीन अलग टीम बनाई गई। इसके अलावा नेपाल और पश्चिम बंगाल में भी उनकी संपत्तियों के सुराग मिले हैं। इसको लेकर ईओयू मुख्यालय के स्तर पर स्थानीय सिविल और पुलिस प्रशासन से संपर्क साधा गया है। बताया जा रहा है कि एडिशनल एसपी के नेतृत्व में ईओयू की एक टीम किशनगंज में लगातार कैंप किए हुए है।

सफेदपोशों की संपत्तियां भी खंगाली जाएगी

किशनगंज एसडीपीओ गौतम कुमार की आय से अधिक संपत्ति से जुड़े दर्ज मामले की छानबीन के दौरान इंओयू को कई माफिया और सफेदपोशों से उनके संबंधों की जानकारी मिली है। एसडीपीओ के नंबरों से दूसरे नंबरों पर दिन भर में 50 बार कॉल किए जाने संबंधित साक्ष्य मिले हैं। इन सबका भी सत्यापन हो रहा है। जांच में पता चला है कि एसडीपीओ ने दूसरों के नाम, संस्था और उनके परिवार के लोगों के नाम पर कई जगह बेनामी संपत्तियां बनाई हैं। ऐसे में उनसे संबंध रखने वाले माफिया और सफेदपोशों की संपत्तियां भी खंगाली जाएगी।

ईरान-अमरीका में सीजफायर पर नहीं बनी बात!

नई दिल्ली (एजेंसी)। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच सीजफायर और ईरान द्वारा होर्मुज स्ट्रेट फिर से खोलने की खबरें सामने आ रही थी। इस बीच ईरान ने अस्थायी युद्ध-विराम के बदले होर्मुज स्ट्रेट को खोलने से इनकार कर दिया है। एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि ईरान अस्थायी संघर्ष-विराम के बदले में होर्मुज स्ट्रेट को फिर से नहीं खोलेगा। उन्होंने आगे कहा कि तेहरान का मानना है कि वाशिंगटन गलत है।

पाकिस्तान ने तैयार किया सीजफायर का प्लान

बता दें कि इससे पहले रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से बताया था कि ईरान और अमेरिका के बीच दुश्मनी खत्म करने का फ्रेमवर्क पाकिस्तान ने तैयार किया है। जिसके बाद पाकिस्तान ने इसे रातों-रात ईरान और अमेरिका के साथ शेयर किया है। जिसमें तुरंत सीजफायर के बाद क कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट के साथ टू-लेयर अप्रोच की आउटलाइन है। यह प्लान सोमवार से लागू हो सकता है, जिसके बाद ईरान होर्मुज को फिर से खोल सकता है। इससे भी पहले रविवार को एक्सियोस ने रिपोर्ट दी थी।

ई-स्कूटर अनुदान योजना से दमोह की सायरा बी बनीं आत्मनिर्भर

भोपाल (नप्र)। श्रम विभाग द्वारा संचालित ई-स्कूटर अनुदान योजना 2024 श्रमिकों के जीवन में परिवर्तन का एक प्रभावी माध्यम बनकर उभर रही है। दमोह में गत दिनों महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने श्रमिक महिला सायरा बी को ई-स्कूटर की चाबी प्रदान की। अब उनका जीवन रोज के कामकाज के लिये किसी सहारे का मोहताज नहीं रहा।

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल द्वारा संचालित इस योजना में सायरा बी को 40 हजार रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। इस सहयोग से अब उनके लिए आवागमन आसान हो गया है, जिससे उनके जीवन स्तर में भी सकारात्मक सुधार आया है।

ई-स्कूटर अनुदान योजना विशेष रूप से श्रमिक परिवारों, खासकर महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो रही है। इससे न केवल उनकी दैनिक जीवन की कठिनाइयाँ कम हो रही हैं, बल्कि वे आत्मनिर्भर बनकर समाज में अपनी मजबूत पहचान भी स्थापित कर रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार की योजनाएं महिला सशक्तिकरण को नई दिशा देती हैं और ग्रामीण व अर्ध-शहरी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को गति प्रदान करती हैं। ई-स्कूटर अनुदान योजना-2024 श्रमिकों के जीवन में सुविधा, आत्मनिर्भरता और सम्मान का नया अध्याय जोड़ रही है। यह पहल 'श्रमिक सशक्त, समृद्ध देश, विकसित मध्यप्रदेश' की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक सशक्त कदम है।

बड़ा तालाब किनारे अतिक्रमण पर जेसीबी चली

भदभदा क्षेत्र की दुकानों पर कार्रवाई, 347 कब्जे लिस्टेड किए, 15 दिन में हटाएगा प्रशासन

भोपाल (नप्र)। भोपाल के बड़ा तालाब को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए जिला प्रशासन ने सोमवार सुबह कार्रवाई शुरू कर दी। भदभदा क्षेत्र में टीम पहुंची और 9 दुकानों को हटाने की कार्रवाई की गई। प्रशासन ने तालाब के चारों ओर कुल 347 अतिक्रमण चिन्हित किए हैं, जिन्हें अगले 15 दिनों में हटाया जाएगा।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भोज वेटलैंड रूल्स लागू होने (16 मार्च 2022) के बाद बने सभी निर्माण हटाए जाएंगे। बड़ा तालाब के एफटीएल (फुल टैंक लेवल) से 50 मीटर तक के अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है।

पिछले दो महीने से जिला प्रशासन अतिक्रमण को चिह्नित कर रहा था। टीटी नगर एसडीएम वृत्त के गौरा गांव, बिसनखेड़ी में सबसे ज्यादा कब्जे सामने आए थे। वहीं, बैरागढ़, बहेटा में भी लोगों ने तालाब की सीमा पर निर्माण कर लिए हैं।

एसडीएम अर्चना शर्मा द्वारा नोटिस दिए जाने के बाद कई लोगों ने खुद ही अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया। मौके पर भारी भीड़ जुटी, जिसे देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है।

प्रशासन की चेतावनी, लोगों ने हटाने का काम शुरू किया

भदभदा क्षेत्र में बड़ा तालाब में आ रहे मकान और दुकानों को लेकर एसडीएम अर्चना शर्मा ने नोटिस दिए थे। इसके चलते सोमवार को कई लोगों ने अपने हाथों से अतिक्रमण हटाना शुरू किया। मौके पर काफी भीड़ भी इकट्ठा हो गई। इसके चलते पुलिस बल तैनात किया गया है। ताकि, किसी भी प्रकार के हंगामे की स्थिति में कार्रवाई की जा सके।

मामला एनजीटी तक पहुंचने की तैयारी

पर्यावरणविद् राशिद नूर के मुताबिक मामला गंभीर है और इसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में उठाया जाएगा।

गांवों में सबसे ज्यादा कब्जे

टीटी नगर एसडीएम सर्कल के गौरा गांव और बिसनखेड़ी में सबसे ज्यादा अतिक्रमण सामने आए हैं। इसके अलावा बैरागढ़ और बहेटा क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर निर्माण किए गए हैं।वन विहार नेशनल पार्क क्षेत्र में भी सीमांकन के दौरान करीब 2.5 किमी में 100 से ज्यादा पिलर लगाए जाने की बात सामने आई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्माण वेटलैंड नियमों के खिलाफ हो सकता है।

प्रदेश में 9 अप्रैल तक आंधी-बारिश का दौर

ग्वालियर समेत 24 जिलों में रहेगा असर, आज से नया सिस्टम एक्टिव होगा

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन यानी, 9 अप्रैल तक आंधी-बारिश का दौर जारी रहेगा। टर्फ के सक्रिय होने से सोमवार को ग्वालियर-चंबल, जबलपुर, रीवा और शहडोल और सागर संभाग के 24 जिलों में असर बना रहेगा। (मौसम केंद्र) भोपाल के अनुसार, 7 अप्रैल से नया सिस्टम एक्टिव हो रहा है।

सोमवार को जिन जिलों में आंधी, बारिश और गरज-चमक का अलर्ट है, उनमें ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, मैहर, कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, सिवनी और बालाघाट शामिल है।

सीनियर मौसम वैज्ञानिक डॉ. दिव्या ई. सुरेंद्रन ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में सिस्टम की एक्टिविटी देखने को मिल रही है। वहीं, 7 अप्रैल से एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस (पश्चिमी विक्षोभ) भी सक्रिय होगा। इसकी वजह से कहीं आंधी चलेगी तो कहीं बारिश हो सकती है।

अगले 4 दिन ऐसा रहेगा एमपी में मौसम

इससे पहले 4 और 5 अप्रैल को प्रदेश में सिस्टम की स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी देखने को मिली है। शनिवार को 14 जिलों में ओलावृष्टि और 39 जिलों में तेज आंधी-बारिश का दौर रहा।

जिन जिलों में बारिश हुई, उनमें ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, सागर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, पन्ना, जबलपुर, डिंडौरी, मंडला, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सिवनी, अनूपपुर, सतना, मैहर, रीवा, मऊगंज, सीधी, कटनी, बड़वानी, बैतूल, नर्मदापुरम, रायसेन, भोपाल, विदिशा, राजगढ़, खरगोन, धार, इंदौर, मंदसौर और खंडवा शामिल हैं।

वहीं, मंदसौर, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, छतरपुर, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, बैतूल, नरसिंहपुर और सागर जिलों में ओले गिरे हैं। दूसरी ओर, कई जिलों में तेज आंधी का दौर भी रहा है।

50 से 60 किमी/घंटा से चलेगी आंधी

मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में तेज आंधी भी चलेगी। कुछ जिलों में इसकी अधिकतम रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रतिघंटा तक रहेगी। बाकी में 30 से 40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चलेगी।

मंत्री विश्वास सारंग के सरकारी बंगले में चोरी

स्टोर रूम में रखी शील्ड-ट्रॉफियां उड़ा ले गए चोर, सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे थे

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश के खेल एवं सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग के सरकारी बंगले में चोरी हो गई है। बंगला परिसर में बने स्टोर रूम से अज्ञात चोर ट्रॉफियां, मोमेंटो और शील्ड उड़ा ले गए हैं। वारदात 2 और 3 अप्रैल की दरमियानी रात की है। इसका खुलासा 6 अप्रैल की सुबह हुआ है।

टीटीनगर पुलिस के मुताबिक, 3 अप्रैल की सुबह बंगले के स्टोर रूम का ताला टूटा मिला। सिक्योरिटी गार्ड ने देखा तो सामान गायब था।

थाना प्रभारी गौरव दोहरे ने बताया कि चोरी गई ट्रॉफियां, मोमेंटो और शील्ड मंत्री सारंग को अलग-अलग कार्यक्रमों में सम्मान स्वरूप मिले थे। फिलहाल, इनकी कीमत का आकलन किया जा रहा है।जांच में सामने आया है कि जिस स्टोर रूम में चोरी हुई, वहां सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं। इससे आरोपियों की पहचान में दिक्कत आ रही है।दोहरे ने कहा- पुलिस आसपास की सड़कों और मकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा।

भोपाल का ट्रैफिक सिस्टम चरमराया

बायपास बंद, शहर में घुसे हजारों ट्रक, वीआईपी रोड और केबल स्टे ब्रिज पर बढ़ा लोड

भोपाल (नप्र)। भोपाल में ट्रैफिक व्यवस्था इन दिनों अचानक बढ़े दबाव से जूझ रही है। सूखी सेवनिया रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) पर मेंटेनेंस कार्य के चलते बायपास बंद होने के बाद भारी वाहनों का रुख शहर के भीतर की ओर हो गया है। इसका सीधा असर वीआईपी रोड और केबल स्टे ब्रिज पर दिख रहा है, जहां लगातार दबाव से संरचनात्मक जोखिम बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।

रात 11 से सुबह 4 बजे तक जाम का पहरा

पिछले एक हफ्ते से शहर में रात होते ही ट्रैफिक बेकाबू हो रहा है। रात 11 बजे के बाद भारी वाहनों की एंट्री बढ़ते ही पॉलिटेक्निक चौराहा से वीआईपी रोड की ओर जाने वाली सड़क जाम हो जाती है। यह जाम केबल स्टे ब्रिज पार करते हुए बिहार सभा तक पहुंच जाता है और हालात तड़के 4 बजे तक जस के तस बने रहते हैं।

लालघाटी से कमला पार्क तक रेंगता ट्रैफिक

लालघाटी से आने वाले भारी वाहनों ने शहरवासियों की परेशानी बढ़ा दी है। खानू गांव से लेकर कमला पार्क तक लंबा जाम लग रहा है। प्रमुख सिग्नलों पर लोगों को कई-कई मिनट तक इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है।

केबल स्टे ब्रिज पर 'रेड अलर्ट'

विशेषज्ञों का कहना है कि केबल स्टे ब्रिज को इस तरह के लगातार भारी लोड के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। स्ट्रक्चर इंजीनियरों के मुताबिक, लगातार दबाव से ब्रिज के केबल और डेक पर असर पड़ सकता है। यदि समय रहते ट्रैफिक को डायवर्ट या नियंत्रित नहीं किया गया, तो लंबे समय में बड़े नुकसान की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

दिन में भी असर: सड़कें टूटने लगीं, रफ्तार थमी

हालांकि भारी वाहनों की आवाजाही रात में ज्यादा है, लेकिन उसका असर पूरे दिन दिख रहा है। शहर की मुख्य सड़कों पर ट्रक-ट्रेलरों की लंबी कतारें नजर आ रही हैं। इससे ट्रैफिक की रफ्तार थम गई है और सड़कों की हालत भी तेजी से बिगड़ने लगी है।

मंत्रालय में प्रतिभा सम्मान समारोह आज

भोपाल। मंत्रालय वल्लभ भवन क्रमांक 01 पांचवीं मंजिल स्थित कक्ष क्रमांक 506 में 7 अप्रैल को एक बार फिर से प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन मंत्रालय सेवा अधिकारी कर्मचारी संघ द्वारा किया जा रहा है। इस वर्ष प्रतिभाशाली बच्चों के अलावा स्वयं को खतरे में डालकर मंत्रालय में लगी आग बुझाने वाले को भी सम्मानित किया जायेगा। इसके अलावा दो कर्मचारी श्री ओपी शर्मा और श्रीमती कविता शिरोले, जिनकी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं को भी सम्मानित किया जायेगा। साथ ही खेलकूद में पदक जीतने वाले कर्मचारी तथा प्रत्येक महीने के प्रथम कार्य दिवस पर मंत्रालय के सामने वंदे मातरम् गायन करने वाली टीम को भी सम्मानित किया जा रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपमुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल रहेंगे। क्षेत्रीय विधायक भगवान दास सबनानी जी को भी आमंत्रित किया गया है कर्मचारी मुद्दे प्रमुखता से उठाने वाले पत्रकार साथियों को भी सम्मानित किया जायेगा। यह जानकारी मंत्रालय सेवा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक ने दी।

बाल विवाह पर सख्ती- अक्षय तृतीया से पहले सभी जिलों में कंट्रोल रूम और उड़न दस्ते बनाने के निर्देश

भोपाल (नप्र)। अक्षय तृतीया के अवसर पर होने वाले सामूहिक विवाह में बाल विवाहों को रोकने के लिए राज्य सरकार ने विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। सचिव महिला एवं बाल विकास श्रीमती जी वी रश्मि ने सभी कलेक्टरों को पत्र लिखकर बाल विवाह रोकथाम के लिए व्यापक अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत प्रदेश में बाल विवाह की घटनाओं को शून्य करने और किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण नेशनल फ़ैमिली हेल्थ सर्वे-5 के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में बाल विवाह के मामलों में कमी आई है, लेकिन कुछ जिलों में अभी भी यह समस्या बनी हुई है। अक्षय तृतीया इस वर्ष 20 अप्रैल 2026 को है और इस दिन प्रदेश में बड़ी संख्या में सामूहिक विवाह आयोजित होते हैं। ऐसे आयोजनों में बाल विवाह होने की संभावना को देखते हुए प्रशासन को विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।

निर्देशानुसार स्कूलों और कॉलेजों में विद्यार्थियों को बाल विवाह के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया जाएगा। 20 अप्रैल को ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में पंच, सरपंच, सचिव और पार्षद बाल विवाह नहीं होने देने की शपथ लेंगे तथा पंचायत और वार्ड कार्यालयों में इसका प्रचार-प्रसार किया जाएगा। इसके अलावा स्कूलों और आंगनबाड़ी के बच्चों की जागरूकता रैलियां भी निकाली जाएंगी।

गांवों में स्व-सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा समूह चर्चा आयोजित कर परिवारों को बाल विवाह न करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, ग्राम कोटवार और पंचायत सचिव की मदद से 18 वर्ष से कम उम्र की किशोरियों की सूची तैयार कर संबंधित परिवारों को समझाइश दी जाएगी तथा उन पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। बाल विवाह की सूचना देने के लिए हेल्पलाइन नंबर 181, 1098 और 112 का व्यापक प्रचार करने के निर्देश दिए हैं।

घर का ताला तोड़ा, कीमती सामान को हाथ तक नहीं लगाया

रीवा (नप्र)। मिडिल ईस्ट में उपजे तनाव के कारण लोगों के सामने एलपीजी का संकट है। कई दिनों के इंतजार के बाद भी लोगों को गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। इसी बीच घरों से गैस सिलेंडर चोरी का मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एक घर से गैस सिलेंडर की चोरी हुई है। घर से कीमती सामान होने के बाद भी चोर केवल सिलेंडर उठाकर ले गया है।

चोरहटा थाना क्षेत्र का मामला- दरअसल, मामला रीवा जिले के चोरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत करहिया मोहल्ले का है। कमलेश साहू ने बताया कि वह किराए के मकान में रहते हैं और मजदूरी करने अपना घर चलाते हैं। कमलेश साहू ने बताया कि उनके घर में चोरी हुई है लेकिन चोर ने किसी भी दूसरे सामान को हाथ नहीं लगाया वह केवल भरा हुआ सिलेंडर लेकर गया है।

कमलेश ने दर्ज कराई शिकायत

कमलेश ने बताया कि वह मजदूरी करने के लिए अपने घर में ताला बंद करके शहर गया था। इसी दौरान उसके घर में किसी चोर ने धावा बोल दिया। शाम को जब कमलेश साहू मजदूरी घर वापस लौटा तो देखा कि घर का ताला टूटा हुआ है और गैस सिलेंडर नहीं था। जिसके बाद उसने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाल गया। जिसमें उसके घर में हुई चोरी की घटना दिखाई थी। इसके बाद कमलेश चोरहटा थाना पहुंचा और अज्ञात के खिलाफ गैस सिलेंडर के चोरी की शिकायत लिखवाई। पुलिस ने मामले की शिकायत दर्ज कर ली है।

कमलेश ने पुलिस को बताया कि चोर उसके घर से केवल गैस सिलेंडर उठाकर ले गया। हैरानी की बात यह है कि घर में और सामान भी था जिसको चोर ने हाथ भी नहीं लगाया।

सिलेंडर ले जाते दिखा चोर

गैस सिलेंडर चोरी कर ले जाते हुए की पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है। जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया है उसमें दिख रहा है एक युवक मुंह पर कपड़ा बांधकर कमलेश के कमरे में घुसता है। कुछ ही समय बाद वह सिलेंडर की टंकी लेकर बाहर की ओर आता है और फिर उसे उठाकर चल देता है।

संपादकीय

रक्षा बाजार: भारत का प्रभावी दखल

अहिंसा के प्रबल पैरोकार महात्मा गांधी के देश भारत में यह खबर यूं तो नकारात्मक ही है, लेकिन व्यावसायिक धमक और वर्तमान वैश्विक परिदृश्य के चलते आर्थिकी के लिहाज से महत्वपूर्ण है। अर्थात् किसी समय शक्तिशाली सेना रखने के पक्ष में नहीं रहा भारत अब वैश्विक रक्षा बाजार का बड़ा खिलाड़ी बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। इसका सबूत हैं आंकड़े। वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा निर्यात 38,424 करोड़ रुपये के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया, जो पिछले वर्ष से 60 फीसदी अधिक है। अगर आगे भी यही गति रही तो भविष्य में भारत वैश्विक रक्षा बाजार में मजबूत खिलाड़ी बन सकता है। अब चुनौती इसे दीर्घकालिक रणनीतिक लाभ में बदलने की है। खास बात यह शिफ्ट है कि हम अब बड़े रक्षा आयातक से उभरते हुए रक्षा निर्यातक के रूप में तब्दील हो रहे हैं। इससे जहां हमारी स्वयं की रक्षा तैयारियों को बल मिलेगा, वहीं हमारी रणनीतिक स्वायत्तता भी कायम रहेगी। आज भारत न केवल अपनी जरूरतों को घरेलू स्तर पर पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है।

पिछले पांच वर्षों में रक्षा निर्यात लगभग तीन गुना हो चुका है, जो यह दर्शाता है कि यह वृद्धि अस्थायी नहीं, बल्कि दीर्घकालिक प्रवृत्ति का हिस्सा है। साथ ही, भारत अब 80 से अधिक देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है, जो वैश्विक स्तर पर भारतीय उत्पादों के प्रति बढ़ते भरोसे का ही संकेत है। इस वृद्धि का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसमें सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रों का संतुलित योगदान है। रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (डीपीएसयू) ने कुल निर्यात में लगभग 55 प्रतिशत योगदान दिया है और उनके निर्यात में 151 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। निजी क्षेत्र ने करीब 45 फीसदी हिस्सेदारी के साथ स्थिर वृद्धि बनाए रखी है। यह साझेदारी संकेत है कि भारत का रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र अब अधिक समन्वित और सक्षम हो रहा है, जहां सरकारी संस्थानों की क्षमता और निजी क्षेत्र की नवाचार क्षमता एक साथ काम कर रही है। भारत द्वारा निर्यात किए जाने वाले रक्षा उत्पादों की प्रकृति में भी बदलाव आया है। अब भारत केवल छोटे पुर्जों या चुनिंदा तकनीकी उत्पादों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्नत रक्षा प्रणालियां और प्लेटफॉर्म भी निर्यात कर रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल, तेजस लड़ाकू विमान, आकाश वायु रक्षा प्रणाली और पिनाका रॉकेट प्रणाली जैसे उत्पादों की वैश्विक मांग बढ़ रही है। दक्षिण-पूर्व एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देशों द्वारा इन प्रणालियों में रुचि दिखाना इस बात का प्रमाण है कि भारत अब वैश्विक रक्षा बाजार में एक विश्वसनीय विकल्प बन रहा है। यह परिवर्तन केवल औद्योगिक क्षमता का परिणाम नहीं है, बल्कि इसके पीछे सरकार के नीतिगत सुधार भी महत्वपूर्ण हैं। रक्षा निर्यात प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है, ऑनलाइन मंजूरी प्रणाली लागू की गई है और मानक संचालन प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी बनाया गया है। इन सुधारों के कारण रक्षा निर्यातकों की संख्या 128 से बढ़कर 145 हो गई है। राजनीतिक स्तर पर यह परिवर्तन आत्मनिर्भरता की उस व्यापक दृष्टि से जुड़ा हुआ है, जिसे प्रधानमंत्री ने 'आत्मनिर्भर भारत' के रूप में प्रस्तुत किया है। इस सकारात्मक तस्वीर के बावजूद कुछ चुनौतियां भी हैं। भारत अब भी अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे स्थापित रक्षा निर्यातकों से पीछे है। गुणवत्ता नियंत्रण, समय पर आपूर्ति और बिक्री के बाद सेवाओं में सुधार की आवश्यकता है। हमे शोध और विकास पर ज्यादा ध्यान देना होगा। इस पर ज्यादा निवेश करना होगा। हमारे रक्षा उत्पाद उच्च गुणवत्ता के और अत्यंत भरोसेमंद होने चाहिए। हम युद्ध के समर्थक नहीं हैं, लेकिन युद्ध में कमतर साबित भी नहीं हो सकते।

युद्ध : ताकत से ज्यादा रणनीति की अहमियत

नजरिया

अंशुमान

लेखक संसद टीवी से सम्बद्ध पत्रकार हैं।

रूस-यूक्रेन युद्ध और अमेरिका-इज़राइल-ईरान टकराव को साथ में देखें, तो आज के युद्ध की असली तस्वीर और भी साफ समझ में आती है। एक तरफ ऐसा युद्ध है जो लंबे समय तक चलता है, जहां धीरे-धीरे ताकत आज़माई जाती है और दोनों पक्ष एक-दूसरे को थकाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ ऐसा टकराव है जो तेज, अचानक और एक साथ कई मोर्चों पर जमीन, हवा, समुद्र, साइबर और स्पेस पर लड़ा जा रहा है। लेकिन इन दोनों को मिलाकर देखें तो एक बड़ी सच्चाई सामने आती हैकि आज के युद्ध न तो आसान रहे हैं और न ही जल्दी खत्म होते हैं। वे ज्यादा जटिल, फैले हुए और अनिश्चित हो गए हैं, जहां नतीजा सिर्फ सैन्य ताकत से नहीं बल्कि धैर्य, सही रणनीति और बदलते हालात के हिसाब से खुद को ढालने की क्षमता से तय होता है।

यूक्रेन का युद्ध इस बदलाव का सबसे बड़ा उदाहरण है। यह अब एक लंबी और थकाने वाली लड़ाई बन चुका है, जहां दोनों पक्ष लगातार एक-दूसरे को कमजोर करने में लगे हैं। पहले के युद्धों में बड़े टैंक, भारी हथियार और विशाल सेनाएं जीत का फैसला करती थीं, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। आज सस्ते ड्रोन, निगरानी तकनीक, सैटेलाइट और सटीक हमले ज्यादा असरदार साबित हो रहे हैं। छोटे-छोटे ड्रोन भी बड़े हथियारों को निशाना बना सकते हैं और युद्ध के मैदान की पूरी जानकारी दे सकते हैं।

रूस ने शुरुआत में सोचा था कि वह जल्दी जीत जाएगा, लेकिन उसने यूक्रेन की तैयारी, उसके मनोबल और पश्चिमी देशों के समर्थन को कम आंका। यही वजह है कि युद्ध लंबा खिंच गया और रूस को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। उसे यह समझ में आया कि अब सिर्फ ताकत के दम पर जीत हासिल करना आसान नहीं है, बल्कि लंबी लड़ाई के लिए खुद को तैयार करना जरूरी है।

पूरे विश्व ने देखा कि यूक्रेन की ताकत सिर्फ उसकी सेना नहीं है, बल्कि उसे मिलने वाला बाहरी समर्थन भी है। अमेरिका और यूरोपीय देशों से मिल रही सैन्य, आर्थिक और खुफिया मदद ने उसे मजबूती दी है। इस मदद ने युद्ध को खत्म तो नहीं किया, लेकिन यह जरूर सुनिश्चित किया कि यूक्रेन हार न माने। इस तरह यह युद्ध 'कौन ज्यादा समय तक टिक सकता है' की परीक्षा बन गया है। यह धैर्य, संसाधन और इच्छाशक्ति की लड़ाई है।

इस युद्ध ने एक और बड़ा बदलाव दिखाया है वह यह है कि अब युद्ध में कुछ भी छिपाना लगभग असंभव हो गया है। सैटेलाइट, ओपन-सोर्स जानकारी और सोशल मीडिया की वजह से हर गतिविधि पर नजर रखी जा सकती है। सेना कहां तैनात है, हथियार कहां जा रहे हैं इन सबका अंदाजा पहले से लगाया जा सकता है। ड्रोन ने युद्ध को और पारदर्शी और खतरनाक बना दिया है। अब हर समय निगरानी रहती है और किसी भी गलती की कीमत तुरंत चुकानी पड़ती है। ऐसे माहौल में सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि तकनीक और लचीलापन असली ताकत बन गए हैं।

वर्तमान हालात देखें तो अमेरिका-ईरान टकराव एक अलग तरह की लड़ाई दिखाता है। यह लड़ाई बहुत तेज, सटीक और एक साथ कई स्तरों पर लड़ी जाती है। इसमें सिर्फ बमबारी ही नहीं होती, बल्कि साइबर हमले, इलेक्ट्रॉनिक तकनीक और सैटेलाइट का भी इस्तेमाल किया जाता है। शुरुआत में ही दुश्मन के अहम ठिकानों, सैन्य ढांचे और कमांड सिस्टम को निशाना बनाकर उसकी जवाब देने की ताकत को कमजोर करने की कोशिश होती है। इससे साफ समझ आता है कि अगर योजना और तकनीक मजबूत हो, तो कम समय में भी बड़ा असर डाला जा सकता है।

लेकिन इस तरह की तेज कार्रवाई का मतलब यह नहीं है कि पूरी जीत मिल ही जाएगी। ईरान ने भी अपने तरीके से मिसाइल हमलों, ड्रोन के झुंड और अपने सहयोगी समूहों के जरिए माकूल जवाब दिया। लेकिन ईरान ने खासतौर पर उन जगहों को निशाना बनाया जो दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अहम हैं, जैसे तेल सप्लाई के रास्ते और समुद्री मार्ग। इसका असर सिर्फ उसी इलाके तक सीमित नहीं रहा, बल्कि तेल की कीमतें बढ़ गईं और दुनिया भर में चिंता बढ़ गई। इससे साफ होता है कि आज के युद्ध सिर्फ सीमाओं के भीतर नहीं रहते, बल्कि उनका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है।यही कारण है कि अब बड़े देश भी अपने कदम सोच-समझकर उठाते हैं। वे यह कोशिश करते हैं कि युद्ध एक सीमा के अंदर रहे और पूरी तरह बेकाबू न हो जाए। यानी अब युद्ध सिर्फ जीतने का नहीं, बल्कि उसे नियंत्रित रखने का भी खेल बन गया है। कब हमला करना है, कितना आगे बढ़ना है और कब रुकना है, ये फैसले भी बेहद महत्वपूर्ण हो गए हैं।

इन दोनों युद्धों से एक अहम बात साफ होती है कि अब कोई भी देश आसानी से और जल्दी युद्ध नहीं जीत सकता। अगर सामने वाला देश समझदारी से काम ले, नई तकनीक अपनाए और अलग तरह की रणनीतियां इस्तेमाल करे, तो वह बड़ी ताकत को भी लंबे समय तक उलझाए रख सकता है। यानी आज के दौर में जो देश कमजोर दिखता है, वह भी सही रणनीति और तकनीक के सहारे मजबूत चुनौती दे सकता है।

रणनीतिक स्तर पर अब युद्ध सिर्फ सेना का खेल नहीं रह गया है। मजबूत गठबंधन, आर्थिक ताकत, ऊर्जा सुरक्षा और कूटनीति भी उतनी ही जरूरी हो गई है। यूक्रेन की ताकत उसके सहयोगियों के समर्थन से बढ़ी है, जबकि अमेरिका की ताकत उसके साझेदार देशों के साथ मिलकर काम करने में दिखती है। इसके उलट, जो देश अकेले पड़ जाते हैं, उनकी स्थिति कमजोर हो जाती है और उनके पास विकल्प कम हो जाते हैं। आज के दौर में जानकारी भी एक बड़ा हथियार बन गई है। आज के समय में सोशल मीडिया, खबरें और साइबर हमले भी युद्ध का अहम हिस्सा बन चुके हैं। इनके जरिए लोगों की सोच प्रभावित की जाती है और दुनिया के दूसरे देशों का समर्थन भी तय होता है। कई बार असली लड़ाई मैदान में नहीं, बल्कि लोगों की सोच और धारणा को लेकर लड़ी जाती है।

अगर ऑपरेशनल स्तर की भी बात करें तो भी युद्ध का स्वरूप पूरी तरह बदल गया है। अब लड़ाई सिर्फ जमीन, हवा और समुद्र तक सीमित नहीं है, बल्कि साइबर स्पेस और सैटेलाइट तक फैल चुकी है। जो देश इन सभी क्षेत्रों में एक साथ काम कर सकता है, उसे बढ़त मिलती है। साथ ही, सप्लाई सिस्टम को भी ज्यादा मजबूत और सुरक्षित बनाना पड़ता है, क्योंकि दुश्मन अब सटीक हमलों से इन्हें निशाना बना सकता है। टैक्टिकल स्तर पर सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब कम लागत में भी बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। सस्ते ड्रोन, छोटे मिसाइल सिस्टम और ऑटोमेटेड हथियारों ने युद्ध के स्वरूप को बदल दिया है। अब छोटे देश या कमजोर पक्ष भी बड़ी ताकतों को चुनौती दे सकते हैं। युद्ध का मैदान ऐसा हो गया है, जहां हर समय खतरा बना रहता है और किसी भी समय हमला हो सकता है। इन सबमें सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब युद्ध सिर्फ सैनिकों तक सीमित नहीं रहा। इसका असर पूरे समाज और देश पर पड़ता है। बिजली, इंटरनेट, बैंकिंग सिस्टम और जरूरी सेवाएं भी निशाने पर आ सकती हैं। यानी आधुनिक युद्ध में पूरा देश किसी न किसी रूप में शामिल हो जाता है।

चाहे रूस-यूक्रेन का युद्ध हो या अमेरिका-इज़राइल-ईरान का युद्ध इन दोनों युद्धों से एक बहुत स्पष्ट और गहरी सीख सामने आती है कि आज के समय में युद्ध का कोई सीधा या आसान रास्ता नहीं बचा है। सिर्फ सैन्य ताकत के भरोसे जीत हासिल करना अब लगभग असंभव हो गया है। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि कौन देश कितनी तेजी से सीखता है, बदलती परिस्थितियों को कितनी समझदारी से अपनाता है और दबाव के बीच कितने लंबे समय तक टिके रहने की क्षमता रखता है। आज युद्ध सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं रहा, बल्कि दिमाग, तकनीक, रणनीति और धैर्य की भी परीक्षा बन चुका है। जो देश इन सबका सही संतुलन बना पाता है, वही अंततः बढ़त हासिल करता है।

मुद्दा

राजकुमार सिन्हा

लेखक 'बरगी बांध विस्थापित संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं।

बदइंतजामी से बेहाल प्रदेश के बिजली उपभोक्ता

तेईस साल पहले 'एशियन डेवलपमेंट बैंक' के कर्ज के साथ मिले सलाह-नुमा-निर्देशों को मैदान में उतारने की खातिर 'मध्यप्रदेश विद्युत मंडल' को तीन तरह की कंपनियों में इसलिए विभाजित किया गया था, ताकि इससे मंडल का घाटा कम या समाप्त हो जाएगा। आज सवा दो दशक बाद देखें तो पता चलता है कि उस जमाने का 2100 करोड़ रुपयों का घाटा अब कई गुना बढ़कर करीब 50,000 करोड़ रुपयों तक पहुंच गया है। क्या हैं, इस कारनामे की वजहें? बता रहे हैं, राजकुमार सिन्हा -संपादक

मध्यप्रदेश में कुप्रबंधन और अधिकारियों की लापरवाही के कारण बिजली कंपनी को हुए नुकसान की भरपाई आम उपभोक्ताओं से की जा रही है। बिजली के दाम साल में एक बार तय होते हैं, परंतु असामान्य परिस्थितियों में बिजली उत्पादन सामान्य बनाए रखने के लिए 'फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट' (एफसीए) का प्रावधान किया गया है। बिजली कंपनियां इसी प्रावधान का फायदा उठाती हैं और हर 3 महीने में बिजली की कीमत बढ़ा देती हैं।

मध्यप्रदेश में एक अप्रैल से बिजली की नई दरें लागू हो चुकी हैं, जिसमें 4.8 प्रतिशत की वृद्धि का प्रावधान किया गया है। वृद्धि का मुख्य आधार 'विद्युत वितरण कंपनियों' (डिस्कॉम) द्वारा पेश किया गया 6044 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा है। इस वृद्धि का उद्देश्य बिजली खरीद की लागत, परिचालन व्यय को पूरा करना और बढ़ते हुए नुकसान को कम करना है, जिसे 'मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग' ने मंजूरी दी है। हालांकि कंपनियों ने 10.19 प्रतिशत से अधिक की मांग की थी, लेकिन आयोग ने 4.8 प्रतिशत की वृद्धि को ही मंजूरी दी है। इससे 1.90 करोड़ मध्यम वर्ग और अधिक खपत वाले उपभोक्ताओं को ज्यादा भार महसूस होगा।

यह स्थिति न केवल आर्थिक असमानता बढ़ाती है, बल्कि ऊर्जा न्याय के सिद्धांतों पर भी प्रश्नचिह्न लगाती है। भारत सरकार द्वारा कोयले पर सरचार्ज की समाप्ति, 'जीएसटी' दर का युक्तिकरण और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा थर्मल पावर प्लांट में लगने वाली प्रदूषण नियंत्रक 'फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन' (एफजीडी) तकनीक की अनिवार्यता को खत्म करने के बावजूद बिजली दर कम होने की बजाय बढ़ा दी गई। 'मध्यप्रदेश विद्युत मंडल' के पूर्व अतिरिक्त मुख्य अभियंता राजेन्द्र अग्रवाल ने आयोग से लिखित मांग की थी कि बिजली खरीदी प्रस्ताव व संबंधित पूंजीगत लागत की गहन समीक्षा के बाद ही प्रस्ताव को मंजूरी दी जाए।

मध्यप्रदेश में बिजली की उपलब्धता और खरीदी लंबे समय से विवादों के केंद्र में रही है। जनवरी 2026 के अंत में मध्यप्रदेश सरकार ने निजी कंपनियों के साथ 4,000 मेगावाट बिजली उत्पादन और खरीदी के लिए एक बड़े समझौते पर हस्ताक्षर किया है। कंपनियों ने बिजली की दर 5.83 रुपए प्रति यूनिट तय की है। जानकार बताते हैं कि समझौते के कारण मध्यप्रदेश विद्युत कम्पनियों को 25 साल में एक लाख करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त भुगतान करना होगा, जिसका बोझ आम उपभोक्ताओं पर होगा।

बिजली खरीदी और निजी कंपनियों से हुए महंगे समझौतों के कारण उपभोक्ताओं की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। 'अखिल भारतीय पावर इंजीनियर्स फेडरेशन' के प्रवक्ता वीके गुप्ता का कहना है कि मध्यप्रदेश में औसत बिजली मांग 9000 मेगावाट और अधिकतम मांग 14,500 मेगावाट है, जबकि राज्य ने पहले ही 21,000 मेगावाट के बिजली खरीद करार पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। राजेन्द्र अग्रवाल का कहना है कि राज्य के पास अगले 10 वर्षों के लिए अतिरिक्त बिजली मौजूद है, ऐसे में अनावश्यक समझौते की जरूरत ही नहीं थी।

बिजली दरों में बढ़ोतरी और 'डिस्कॉम' पर बढ़ते वित्तीय दबाव ने राज्य में ऊर्जा प्रबंधन को नई बहस के केंद्र में ला दिया है। ऊंचे दामों पर की जा रही बिजली खरीदी से न सिर्फ घरेलू उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ा है, बल्कि उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भी प्रभावित हो रही है। पिछले कुछ वर्षों से बिजली दरों में लगातार बढ़ोतरी और बिलों में अनियमितताएं आम उपभोक्ताओं, किसानों और छोटे व्यवसायियों के लिए बड़ी समस्या बन चुकी हैं। राज्य की बिजली खरीद नीतियों, निजी कंपनियों से महंगे समझौतों और 'डिस्कॉम' की अक्षमताओं - जैसे लाइनलॉस, बिजली चोरी, प्रबंधन की कमियां और पुराना घाटा - का बोझ सीधे जनता पर पड़ रहा है।

मध्यप्रदेश में बिजली उत्पादन और खरीदी का काम तीन मुख्य स्तरों पर होता है - 'मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी' (जो बिजली खरीद की नोडल एजेंसी है), निजी बिजली कंपनियां और राज्य की सरकारी उत्पादन कंपनियां। 'कैग' की विभिन्न रिपोर्टों में 'पावर मैनेजमेंट कंपनी' की नीतियों पर सवाल उठाए गए हैं, जैसे महंगी दरों पर निजी कंपनियों से बिजली खरीद के अनुबंध। कुछ निजी पावर प्लांट्स से बिजली बाजार दर से अधिक कीमत पर खरीदी गई। अनुबंध के कई प्रावधानों के कारण राज्य को बिना बिजली लिए भी भुगतान करना पड़ता है। एक जानकारी के अनुसार 2020 से 2022 के बीच मध्यप्रदेश सरकार ने निजी कंपनियों को 1,773 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जबकि उनसे एक यूनिट भी बिजली नहीं खरीदी गई।

कुछ अनुबंधों में 'पास-थ्रू' का प्रावधान है, जिससे बढ़ी हुई ईंधन लागत का बोझ सीधे उपभोक्ताओं पर डाल दिया गया। कैप्टिव प्राइवेट प्लांटों से भी बाजार कीमत से अधिक दरों पर बिजली खरीदी गई। जहां बाजार दर 2 से 3 रुपए प्रति यूनिट थी, वहीं 4.50 से 6 रुपए प्रति यूनिट तक भुगतान किया गया। राज्य की अपनी उत्पादन कंपनियों के पास पर्याप्त क्षमता होने के बावजूद निजी प्लांटों से अधिक बिजली खरीदी गई। ऊर्जा अर्थशास्त्रियों के अनुसार ये समझौते 2010 से 2015 के बीच हुए थे, जब कोयले की कीमतें अधिक थीं।

आज बिजली का बाजार सस्ता हो चुका है, लेकिन पुराने अनुबंध राज्य को महंगी बिजली खरीदने के लिए बाध्य कर रहे हैं। नियामक निगरानी भी पर्याप्त मजबूत नहीं मानी जाती। मूल्य निर्धारण और खरीद फैसलों में अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार 200 यूनिट मासिक खपत पर मध्यप्रदेश में लगभग 1,425 रुपए बिल आता है, जबकि छत्तीसगढ़ में 900 रुपए और गुजरात में 785 रुपए है। वहीं 300 यूनिट पर मध्यप्रदेश में 2,342 रुपए, छत्तीसगढ़ में 1,450 और गुजरात में 1,253 रुपए है। कई घरों में औसत घरेलू बिल 15 से 25 प्रतिशत तक बढ़ गया है, जिससे मासिक बजट पर गहरा असर पड़ा है।

विडंबना है कि 'एशियन डेवलपमेंट बैंक' (एडीबी) की सिफारिश (टाटा राव कमिटी) पर 2003 में विद्युत मंडल के घाटे को कम करने के लिए बिजली कंपनियों का गठन किया गया था। वर्ष 2000 में घाटा 2100 करोड़ रुपए था, लेकिन 31 मार्च 2025 तक यह बढ़कर 49,239 करोड़ रुपए और 71,394 करोड़ रुपए हो गया है। ऊर्जा किसी भी राज्य की आर्थिक और सामाजिक प्रगति का आधार होती है। मध्यप्रदेश जैसे राज्य में, जहां कृषि, उद्योग और घरेलू उपभोग बड़े पैमाने पर बिजली पर निर्भर हैं, वहां बिजली दरों में वृद्धि का व्यापक प्रभाव पड़ता है। मध्यप्रदेश में महंगी बिजली का मुख्य कारण उत्पादन और वितरण में पारदर्शिता की कमी, कमजोर निगरानी और जनपक्षीय नीति का अभाव है। वास्तव में सरकार ने ऊर्जा के उत्पादन और वितरण की नीतियों में आम जनता के हितों को प्राथमिकता नहीं दी है। (सप्रेस)

कटाक्ष

श्याम यादव

पत्रकार और व्यंग्यकार

मिलते हैं ब्रेक के बाद

स्कूल में इंटरवल होता है। सिनेमा में इंटरवल होता है। क्रिकेट में टी-ब्रेक, फुटबॉल में हाफ टाइम, दफ्तर में लंच ब्रेक, टीवी पर कमर्शियल ब्रेक। सब जगह ब्रेक है। अब युद्ध में भी ब्रेक है। सीधी बात।

बड़े चौधरी लड़ रहे थे। रोज खबर आ रही थी–आज इतना, कल उतना। माहौल बना हुआ था। अचानक बोले बस, विराम।

कोई खास वजह नहीं बताई।

उनकी इच्छा है। अब इच्छा का क्या है, आती है, चली जाती है।

पहले आई तो युद्ध शुरू हो गया।

अब आई तो युद्ध रुक गया।

बीच में जो लोग मरे, जो शहर जले–वो भी उसी इच्छा के हिस्से में गए होंगे।

हिसाब कहीं तो बनता होगा। किस किताब में बनता है, यह नहीं पता।

और अंदाज देखिए, मानना है तो मानो, नहीं मानना तो भी मानो।

यानी बात यहीं खत्म।

युद्ध अब नियम से नहीं चलता।

चलता है जैसे मन आए।

थोड़ा मार लो। थोड़ा रुक लो।

फिर से मार लो।

जैसे कोई नल खुला है, कभी तेज, कभी बंद।

पानी किसके घर जा रहा है, यह पूछने का टाइम किसी के पास नहीं।

पहले युद्ध का मतलब होता था, या तो खत्म करो, या खत्म हो जाओ।

अब मतलब है, चलाते रहो।

जितना चलता रहेगा, उतना चलता रहेगा, न कोई अंत की जल्दी, न शुरुआत का अफसोस।

इतिहास में भी युद्ध थे। महाभारत था। अठारह दिन चला। दिन में लड़ाई, शाम को विराम। तलवारें नीचे, लोग अपने-अपने डेरे में। एक मर्यादा थी। नियम थे।

अब तलवारें नहीं हैं, मर्यादा नहीं है। बस घोषणा है।

घोषणा भी ऐसी, जैसे मौसम बताया जा रहा हो।

आज हमला रहेगा।

कल हल्की शांति रहेगी।

परसों फिर से बादल घिर सकते हैं।

बचपन में खेलते थे। गली में।

कोई भी बोल देता, बस, ब्रेक।

खेल रुक जाता था।

कोई बहस नहीं।

थोड़ी देर बाद फिर शुरू।

जिसकी बारी थी, वही से खेल पकड़ लेता था।

अब वही खेल बड़ा हो गया है।

बस चीजें असली हो गई हैं।

चोट असली, नुकसान असली, लेकिन अंदाज वही बचपन वाला।

बड़े चौधरी ने चौबीस दिन तक लड़ाई चलाई।

फिर पाँच दिन का ब्रेक।

कारण, सामने वाला कमजोर पड़ रहा है।

कमजोर है तो खत्म करो।

लेकिन नहीं।

उसे थोड़ा संभलने दो।

या शायद खुद संभलने के लिए रुक गए।

कौन जाने।

या फिर, खेल लंबा खींचना है।

ताकि मैदान भी गर्म रहे और दर्शक भी।

जितनी देर तक खेल दिखेगा, उतनी देर तक चर्चा भी चलती रहेगी।

चर्चा चलेगी तो बयान आएंगे।

बयान आएंगे तो माहौल बना रहेगा।

सीधी बात कोई नहीं करता।

सब घुमा के बोलते हैं।

यह ब्रेक किसके लिए है, साफ नहीं।

सामने वाले के लिए?

अपने लिए?

या देखने वालों के लिए?

क्योंकि अब युद्ध सिर्फ लड़ा नहीं जाता, दिखाया भी जाता है।

लगातार दिखाओगे तो लोग ऊब जाएंगे।

बीच में ब्रेक दोगे तो फिर से देखेंगे।

थोड़ा सस्पेंस, थोड़ा इंतज़ार, तभी तो अगली खबर की कीमत बनती है।

वरना रोज-रोज की मारपीट में नया क्या है?

अब युद्ध खबर नहीं रहा।

आदत हो गया है।

सुबह सुन लिया, हमला हुआ।

दोपहर में, जवाबी हमला।

शाम को विराम है।

और आदमी खाना खाकर सो गया।

कोई चौंकता नहीं अब।

यही असली दिक्कत है।

चौंकना खत्म हो जाए तो सवाल भी खत्म हो जाते हैं।

और जब सवाल खत्म हो जाएं, तो जवाब देने वाला और भी आराम से ब्रेक ले लेता है।

युद्ध चल रहा हैज

और बीच-बीच में ब्रेक भी।

जैसे सब तय हो।

जैसे सब ठीक चल रहा हो।

फिलहाल ब्रेक है,

मिलते हैं ब्रेक के बाद।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

श्वान ऊर्जा मिशन : दुम पर सवार दमदार बिजलीघर

व्यंग्य

सुदर्शन कुमार सोनी

लेखक व्यंग्यकार हैं।

'मेरा श्वान, मेरा मान!' आज दुनिया खाड़ी युद्ध की आशंका से पैदा ऊर्जा संकट के अंधेरे में नवकरणीय ऊर्जा के नए-नए स्रोत तलाश रही है। कहीं पेट्रोल गायब, कहीं डीज़ल, कहीं गैस–जैसे चुनाव बाद वादे। विशेषज्ञ सूर्य, पवन, जल की बात करते हैं, पर हमारे देश की गली-गली में घूमता खजाना अब तक अनदेखा है। आईआईटी वाले विदेशी पैकेज की दौड़ छोड़कर अगर श्वान पर रिसर्च करें, तो देश की किस्मत चमक सकती है।

श्वान सदियों से इंसान का साथी रहा है, पर अब वह ऊर्जा संकट का टॉर्च भी बन सकता है। जहाँ इंसान हाथ पर हाथ धरे बैठा है, वहाँ कुत्ता दुम हिलाकर देश में दम भर सकता है। हमारी गलियों में जितने कुत्ते हैं, उतनी संभावनाएँ हैं–हर दुम में छुपा एक छोटा बिजलीघर, जो दिनभर ऐसे हिलता है जैसे सेंसेक्स या नेताओं के बयान–ऊपर-नीचे, पर हमेशा सक्रिय।

सोचिए, 'पूँछ-चक्र' बना दिया जाए, जो हर झटके को बिजली में बदल दे। मालिक घर आए, कुत्ता दुम हिलाए और मीटर दौड़ने लगे–जितना प्यार, उतनी बिजली। बिस्कुट दिखते ही पूँछ की स्पीड बढ़े और उत्पादन भी–अब बिस्कुट इनाम नहीं, ऊर्जा सब्सिडी होगा। नवकरणीय ऊर्जा का नवीनतम स्रोत–श्वान ऊर्जा!

अब बात भौंकने की। हमारे कुत्ते बिना कारण भी भौंकते हैं–शायद टीवी बहसों और सोशल मीडिया से प्रेरित। पर वही भौंक अगर ऊर्जा में बदले, तो नींद भले थोड़ी बहुत डिस्चार्ज हो, बैटरियाँ जरूर चार्ज होंगी। हर 'भौं-भौं' अब शोर नहीं, संसाधन होगी; और दस कुत्ते मिलकर भौंकें, तो वह झुंड नहीं, संगठित ऊर्जा ग्रिड होगा।

सरकार अगर 'श्वान ऊर्जा मिशन' शुरू कर दे, तो 'हर घर जल' के साथ 'हर घर कुत्ता' भी नीति बन जाएगी। आवारा कुत्तों की समस्या का समाधान भी हो जाएगा–नसबंदी पर करोड़ों खर्च करने के बजाय उन्हें ऊर्जा कर्मी बना दीजिए। जहाँ बिजली की किल्लत है, वहाँ लोग सूर्य देवता का इंतजार नहीं करेंगे–धूप न आए तो क्या हुआ, शेरू तो है! शहरों में कुत्ता उसकी नस्ल से नहीं, वॉटेज से पहचाना जाएगा; डॉग शो में सुंदरता नहीं, उत्पादन जीतेगा।

मिशन की शुरुआत भोपाल से हो सकती है–यहाँ के श्वान दुम हिलाने में दक्ष हैं। वैसे मलाईदार पदस्थापना के लिए यहाँ का कर्मी भी बंगलों के सामने दुम हिलाने में माहिर होता है; जो नहीं हिलाता, वह दमदार पोस्टिंग से वंचित रहता है। एक श्वान 100 वाट, गली के 50 श्वान–पूरा मोहल्ला रोशन!

चुनावी राजनीति में नया नारा गूँजेगा–'हर घर जनरेटर-कुत्ता!' पोस्टर पर नेता जी की गोद में बैटरी बंधा श्वान–कैप्शनः 'मेरा श्वान, मेरा मान!' विपक्ष आरोप लगाएगा कि कुछ खास श्वानों को ही योजना का लाभ मिला। सीएम हेल्पलाइन में शिकायतें आएँगी–'हमारे मोहल्ले के कुत्तों की दुम में अभी तक बैटरी नहीं बंधी!' स्टार्टअप भी पीछे नहीं रहेंगे–'श्वान डायनेमो ऐप'- पूँछ हिलाओ, बिटकॉइन कमाओ। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिकेगा 'पेडिग्री पावर-पैक'–24×7 पूँछ-चलित यूपीएस।

जल्द ही भारत जरूरत से ज्यादा बिजली पैदा करने लगेगा। विदेशी पूछेंगे–इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है? हम मुस्कराकर कहेंगे–'हमारे कुत्ते एनरजेटिक हैं।' संसद में बहस होगी–कुत्तों के लिए न्यूनतम पूँछ-हिलाने का मानक क्या हो और भौंकने की सीमा कितनी तय हो–क्योंकि अब वे भी कामकाजी वर्ग में गिने जाएँगे।

अंत में बात इतनी सी है कि जुगाड़ वाले देश में समाधान की कमी नहीं; बस श्वान को सम्मान और उसकी दुम पर थोड़ी सी आस्था चाहिए। वैसे यहाँ इंसान भी दुम हिलाने में पीछे नहीं–बस स्वार्थ पूरा होने की उम्मीद हो। जिसने इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ा, वही अब उसके अंधेरे घर को रोशन करने को तैयार है।

अगली बार जब कोई दुम हिलाए, तो समझ लीजिए–वह सिर्फ खुशी नहीं, देश की ऊर्जा जरूरतों में अपना दमदार योगदान दे रहा है।

विश्व स्वास्थ्य दिवस

डॉ. नरेश गौतम

सहायक प्रोफेसर, समाज कार्य विभाग एसआरयू, रायपुर

भारत की बीमार व्यवस्था व बाजार के हाथ में सेवाएं

कोविड-19 ने इस देश की स्वास्थ्य व्यवस्था की असली तस्वीर सबके सामने ला दी थी। उस समय लोगों के पास वैज्ञानिक जानकारी कम थी, लेकिन सलाह देने वाले बहुत थे। कोई काढ़ा बता रहा था, कोई गोमूत्र पिला रहा था, कोई गोबर से नहाने की बात कर रहा था तो कोई बाबाओं के चमत्कार से ठीक होने की बात कर रहा था और वहीं सत्ता की ताली, थाली और मोमबत्ती के बीच आम आदमी अस्पताल, ऑक्सीजन और दवा के लिए भटकता हुआ दम तोड़ रहा था। बेड नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थी, दवाएँ नहीं थीं और लोग अपने परिजनों को बचाने के लिए दर-दर भटक रहे थे। कोविड ने यह साफ कर दिया कि जब व्यवस्था टूटती है तो बीमारी गरीब और अमीर में भेद नहीं करती, लेकिन इलाज जरूर करता है।

विश्व स्वास्थ्य दिवस 2026 की थीम है 'स्वास्थ्य के लिए एकजुटता और विज्ञान के साथ खड़े होना।' यह केवल एक नारा नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया को यह याद दिलाने की कोशिश है कि स्वास्थ्य को अंधविश्वास, अफवाह, राजनीति और मुनाफे से बचाकर विज्ञान, सहयोग और मानवीय जिम्मेदारी के आधार पर देखा जाना चाहिए। लेकिन भारत की वास्तविकता इन आदर्श शब्दों से बहुत दूर दिखाई देती है। यहाँ आज भी बड़ी संख्या में लोग इलाज के लिए वैज्ञानिक पद्धति से अधिक बाबाओं, झाड़-फूंक, जादू-टोना, घरेलू चमत्कारों और फर्जी डॉक्टरों पर भरोसा करने को मजबूर हैं। यह केवल अशिक्षा का परिणाम नहीं है, बल्कि बेहद बीमार स्वास्थ्य व्यवस्था का परिणाम है। जब अस्पताल महंगे हो जाएँ, डॉक्टर न मिलें, दवाएँ गायब हों और गरीब इलाज के बिना मरने लगे, तब समाज अंधविश्वास की तरफ सुनियोजित तरीके से धकेला जाता है। भारत में बीमारी को अब भी केवल व्यक्ति की निजी समस्या माना जाता है, जबकि बीमारी का संबंध समाज से भी होता है। गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण, प्रदूषण, जहरीला भोजन, खराब पानी, तनाव, असुरक्षित काम और असमानता लोगों को बीमार बनाते हैं। लेकिन हमारी व्यवस्था इन कारणों को देखने के बजाय बीमारी को केवल एक मेडिकल रिपोर्ट तक सीमित कर देती है। हालिया स्टेट ऑफ हेल्थकेयर इन रूरल इंडिया, 2024' की रिपोर्ट में डॉक्टर-रोगी अनुपात लगभग 1:1456 है, जो कि भारत जनसंख्या के अनुसार बहुत खराब स्थिति को दर्शाता है।

कोविड-19 ने इस देश की स्वास्थ्य व्यवस्था की असली तस्वीर सबके सामने ला दी थी। उस समय लोगों के पास वैज्ञानिक जानकारी कम थी, लेकिन सलाह देने वाले बहुत थे। कोई काढ़ा बता रहा था, कोई गोमूत्र पिला रहा था, कोई गोबर से नहाने की बात कर रहा था तो कोई बाबाओं के चमत्कार से ठीक होने की बात कर रहा था और वही सत्ता की ताली, थाली और मोमबत्ती के बीच आम आदमी अस्पताल, ऑक्सीजन और दवा के लिए भटकता हुआ दम तोड़ रहा था। बेड नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थी, दवाएँ नहीं थीं और लोग अपने परिजनों को बचाने के लिए दर-दर भटक रहे थे। कोविड ने यह साफ कर दिया कि जब व्यवस्था टूटती है तो बीमारी गरीब और अमीर में भेद नहीं करती, लेकिन इलाज जरूर करता है। भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था अब दो हिस्सों में बँट चुकी है, गरीबों के लिए सरकारी अस्पताल और अमीरों के लिए निजी अस्पताल। सरकारी अस्पतालों की हालत लगातार बदतर होती जा रही है। डॉक्टरों की कमी, दवाओं की कमी, मशीनों का खराब होना, लंबी लाइनें, गंदगी और भ्रष्टाचार अब आम बात हो चुकी है। ग्रामीण इलाकों में स्थिति और भी भयावह है। हजारों गाँव आज भी ऐसे हैं जहाँ लोगों को इलाज के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों के पद वर्षों से खाली पड़े हैं। कई राज्यों में आधे से ज्यादा सरकारी डॉक्टरों के पद रिक्त हैं। सरकारें स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का दावा जरूर करती हैं, लेकिन बजट कुछ और कहानी कहता है। भारत में सरकारी स्वास्थ्य खर्च अब भी जीडीपी के लगभग 2 से 2.5 प्रतिशत के आसपास ही है। विकसित देशों में यही खर्च 6 से 10 प्रतिशत तक पहुँचता है। इसका सीधा मतलब है कि भारत में स्वास्थ्य को अभी भी बुनियादी अधिकार नहीं, बल्कि खर्च समझा जाता है। इसका सबसे बड़ा असर गरीब और निम्न मध्यम वर्ग पर पड़ता है। बीमारी उन्हें केवल शारीरिक रूप से नहीं तोड़ती, बल्कि आर्थिक रूप से भी तबाह कर देती है। एक गंभीर बीमारी पूरे परिवार को कर्ज में डुबो सकती है। इलाज के लिए लोग जमीन बेचते हैं, गहने गिरवी रखते हैं, रिश्तेदारों से उधार लेते हैं। लाखों लोग हर साल केवल इलाज के खर्च की वजह से गरीबी में चले जाते हैं। निजी अस्पतालों का हाल और भी चिंताजनक है। वहाँ इलाज अब सेवा नहीं, बल्कि एक उद्योग बन चुका है। भर्ती, जांच, ऑपरेशन, आईसीयू, दवा, हर चीज का लंबा बिल बनाया जाता है। कई निजी अस्पताल मरीज की बीमारी से पहले उसकी आर्थिक हैसियत देखते हैं। कोविड के दौरान यह खुलकर सामने आया। एक बेड, एक ऑक्सीजन सिलेंडर, एक इंजेक्शन और एक एम्बुलेंस के लिए हजारों-लाखों रुपये वसूले गए। जिनके पास पैसा था, वे बच गए। जिनके पास पैसा नहीं था, वे अस्पतालों के बाहर दम तोड़ते रहे।

2017 में गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी के बीच 60 से अधिक बच्चों की मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया था। बाद में सामने आया कि ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी का भुगतान महीनों से अटका हुआ था। बार-बार चेतावनी देने के बावजूद प्रशासन और सरकार ने ध्यान नहीं दिया। उस घटना ने दिखाया कि भारत में गरीब की जान कितनी सस्ती है। यह केवल एक अस्पताल की विफलता नहीं थी, बल्कि यह पूरे सिस्टम की सड़ांध का उदाहरण था। आज भी देश के अधिकांश सरकारी अस्पतालों में गरीब मरीजों को बाहर से दवाएँ खरीदनी पड़ती हैं। कई बार मशीनें महीनों खराब रहती हैं। जांच के लिए निजी लैब में भेजा जाता है। डॉक्टर कम हैं, लेकिन मरीजों की लाइनें लंबी हैं। स्वास्थ्य सेवा धीरे-धीरे सरकारी जिम्मेदारी से निकलकर बाजार के हाथों में जा चुकी है। दवा उद्योग का हाल भी कम खतरनाक नहीं है। नकली दवाएँ, एक्सपायरी दवाओं की नई पैकिंग, कमीशन पर दवा लिखना और बिना लाइसेंस के मेडिकल स्टोर भी आम होते जा रहे हैं। कई डॉक्टर वही दवा लिखते हैं, जिस पर उन्हें अधिक कमीशन मिलता है। गरीब मरीज को सस्ती दवा नहीं, बल्कि महंगी दवा खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है। उज्बेकिस्तान, गाम्बिया और भारत में भी भारतीय कंपनियों के कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत की घटनाओं ने भारत की दवा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। सवाल यह नहीं है कि ऐसी दवाएँ बाहर कैसे पहुँचीं, बल्कि यह है कि वे बाजार तक पहुँचती ही क्यों हैं? जाँच कौन करता है? जिम्मेदारी किसकी है? और हर हादसे के बाद केवल जांच समिति बनाकर मामले को दबा क्यों दिया जाता है?

भारत का संविधान हर नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार देता है। अदालतें कई बार कह चुकी हैं कि स्वास्थ्य भी जीवन के अधिकार का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा है कि किसी भी घायल या बीमार व्यक्ति को इलाज देने से अस्पताल मना नहीं कर सकते। लेकिन हकीकत यह है कि आज भी इस देश में गरीब आदमी अस्पताल के दरवाजे पर खड़ा होकर मर जाता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर स्वास्थ्य अधिकार है, तो फिर यह अधिकार केवल पैसे वालों तक क्यों सीमित है? डॉक्टर क्यों नहीं हैं? दवाएँ क्यों नहीं हैं? ऑक्सीजन क्यों नहीं है? ग्रामीण अस्पताल खाली क्यों हैं? और सरकारें सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत करने के बजाय निजी अस्पतालों के लिए जगह क्यों बना रही हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस पर विज्ञान की बात करना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है स्वास्थ्य को बाजार से बचाना। जब तक स्वास्थ्य को मुनाफे की चीज माना जाएगा, तब तक गरीब इलाज के बिना मरता रहेगा और अमीर इलाज खरीदता रहेगा।

सरोकार

डॉ. चन्दर सोनाने

लेखक मप्र जनसंपर्क विभाग के सेवानिवृत अधिकारी हैं।

10 साल में 94 हजार सरकारी स्कूल हुए बंद

हाल ही में एक दुखद खबर आई है। वो खबर यह है कि देश में पिछले एक दशक में 93,779 सरकारी स्कूल बंद हो गए है। वर्ष 2014-2015 में देश में 11,07,101 सरकारी स्कूल चल रहे थे, ये सरकारी स्कूल साल 2024-25 में घटकर 10,13,322 रह गए। आश्चर्यजनक बात यह है कि इसी अवधि में निजी क्षेत्र में 51,419 स्कूल नए खुल गए। उक्त जानकारी किसी प्रायवेट संस्था द्वारा किए गए सर्वे का परिणाम नहीं है, बल्कि केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में दी गई। वर्ष 2014-15 में देश की आबादी करीब 130.9 करोड़ थी। उस समय देश में कुल स्कूल 11,07,101 थे। इन स्कूलों में 14,40,81,075 छात्रों का नामांकन हुआ था। इस प्रकार 93,779 स्कूल बंद हो गए। साल 2024-25 में देश की आबादी लगभग 146.3 करोड़ थी। इस समय देश में कुल स्कूल 10,13,322 रह गए और छात्रों का नामांकन भी घटकर 12,15,89,911 हो गया। इस प्रकार 10 साल के दौरान छात्रों के नामांकन में 2,24,91,164 गिरावट आ गई। यानी करीब सवा दो करोड़ से अधिक छात्र सरकारी स्कूल में पढ़ने से वंचित रह गए।

मजेदार बात यह है कि पिछले 10 सालों में देश में कुल प्रायवेट स्कूल 51419 बढ़ गए। वर्ष 2014-15 में कुल प्रायवेट स्कूल देशभर में 2,88,164 थे। वर्ष 2024-25 में निजी स्कूल बढ़कर 3,39,583 हो गए। नामांकन में भी आश्चर्यजनक बढ़ोत्तरी हो गई। वर्ष 2014-15 में इन निजी स्कूलों में छात्रों का नामांकन 8,46,42,241 थे, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 9,58,56,710 हो गए। इस प्रकार आश्चर्यजनक रूप से पिछले एक दशक में निजी स्कूलों में 1,12,14,469 नामांकन बढ़ गए।

सरकारी स्कूल बंद होने की प्रवृत्ति उत्तरी और पूर्वी राज्यों में ज्यादा है। दक्षिण राज्यों में अपेक्षाकृत कम स्कूल बंद हो रहे हैं। जैसे कि मध्यप्रदेश में पिछले एक दशक में करीब 30 हजार स्कूल बंद हुए हैं। वहीं उत्तरप्रदेश में करीब 25 हजार सरकारी स्कूल बंद हो गए। किन्तु तमिलनाडु में इस दौरान 285 सरकारी स्कूल ही बंद हुए। इसी प्रकार केरल में भी उक्त अवधि में केवल 296 सरकारी स्कूल ही बंद हुए। केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिए गए आँकड़े चिंताजनक है। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को चाहिए कि बंद हो रहे सरकारी स्कूलों के कारणों की पड़ताल करें और जो कमियाँ आए उसे दूर करने का प्रयास करें। यह सर्वज्ञात सत्य है कि सरकारी स्कूलों में गरीब परिवारों के बच्चे ही पढ़ते हैं। इसलिए बंद हो रहे स्कूल के कारण सीधा प्रभाव गरीब परिवारों के बच्चों पर ही पड़ता है। हजारों- लाखों बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। मध्यप्रदेश में हाल ही में 1 अप्रैल से सरकारी स्कूलों में बच्चों के प्रवेश का उत्सव मनाया जा रहा है। पहले दिन स्कूल आने वाले बच्चों को तिलक लगाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। सरकार की यह पहल अच्छी है। किन्तु उन्हें यह सोचना चाहिए कि रोज क्यों बंद हो रहे हैं स्कूल ? बंद हो रहे स्कूल के बच्चे शिक्षा से वंचित क्यों हो रहे है ?

संविधान के अनुसार बच्चों को 8 वीं तक शिक्षा प्राप्त करना उनका मूलभूत अधिकार है। इस प्रकार सीधा-सीधा बच्चों के अधिकारों का हनन हो रहा है। इसे प्राथमिकता से रोका जाना चाहिए। केन्द्र और राज्य सरकार को चाहिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में बंद हुए सरकारी स्कूलों के कारणों का पता लगाएँ। और उन कारणों को प्राथमिकता से दूर करें। देश में अनेक सरकारी प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं, जिसमें कक्षा 1 से 5वीं तक एक ही शिक्षक सभी विषय पढ़ा रहा है। अभी भी कई स्कूल झोपड़ी में या पेड़ के नीचे लग रहे हैं।

भवनविहीन स्कूल के दो उदाहरण ही दिये जाने काफी होंगे। मध्यप्रदेश के सीहोर जिले के आस्टा विकासखंड के ग्राम हरजीपुरा में शासकीय प्रायमरी स्कूल में प्रवेश उत्सव के पहले दिन ही बच्चे खुले आसमान के नीचे धूप में नीम के पेड़ के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। इसी प्रकार संभल में एक प्राथमिक स्कूल ऐसा है, जहां पेड़ के नीचे बैठकर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। जर्जर भवन होने के चलते लगभग 1 वर्ष पहले उसे ध्वस्त कर दिया गया था। मामला उत्तरप्रदेश के संभल के ब्लॉक पंवासा के गांव सिकंदरपुर करछली का है। बीते एक वर्ष से सरकारी विद्यालय का भवन न होने से छात्र-छात्राएं एक पेड़ के नीचे बैठकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिससे स्कूल में पंजीकृत बच्चों में से भी कम बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं।

कई स्कूल ऐसे भी हैं, जिसमें एक भी शिक्षक नहीं है। यानी शिक्षकविहीन स्कूल हैं। ऐसे स्कूलों के बच्चों का भविष्य भगवान भरोसे है। स्कूलों में छात्र और छात्राओं के लिए शौचालय की पृथक-पृथक व्यवस्था करना भी आवश्यक है। इसके साथ ही मूलभूत सुविधाएं भी स्कूलों को उपलब्ध कराना उतना ही जरूरी है। सरकारी स्कूलों की कमियों को जब तक दूर नहीं किया जायेगा, तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। इसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला। बदलाव के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति जरूरी है। और आज इसी की सबसे ज्यादा जरूरत है।

विश्व स्वास्थ्य दिवस पर विशेष

श्वेता गोयल

लेखक शिक्षक हैं।

विलासिता नहीं, एक वैज्ञानिक मानवाधिकार है स्वास्थ्य

स्वास्थ्य की अवधारणा अब केवल रोगों के उपचार तक सीमित नहीं रह गई है। यह एक समग्र दृष्टि है, जिसमें पोषण, स्वच्छता, मानसिक संतुलन, सुरक्षित पर्यावरण और सामाजिक समानता जैसे अनेक आयाम शामिल हैं। एक स्वस्थ समाज वह है, जहां एक गर्भवती महिला को समय पर देखभाल, सम्मान और पोषण मिले; जहां नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद आवश्यक चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो और जहां प्रत्येक नागरिक को जीवन के हर चरण में स्वास्थ्य सेवाओं की सहज उपलब्धता हो। यही कारण है कि आज स्वास्थ्य को वैश्विक स्तर पर एक मौलिक मानव अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है, भले ही इसकी वास्तविक उपलब्धता अब भी एक चुनौती बनी हुई है। वैश्विक परिदृश्य पर नजर डालें तो स्थिति मिश्रित है। एक ओर चिकित्सा विज्ञान ने टीकाकरण, संक्रामक रोगों की रोकथाम, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं और आधुनिक सर्जरी के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, वहीं दूसरी ओर विश्व की बड़ी आबादी अब भी बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित है।

हर वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाने वाला 'विश्व स्वास्थ्य दिवस' मानवता के सामूहिक विवेक को जागृत करने वाला एक वैश्विक अवसर है। इस वर्ष 'विश्व स्वास्थ्य दिवस' की थीम 'स्वास्थ्य के लिए एकजुट। विज्ञान के साथ खड़े रहें'' हमें यह याद दिला रही है कि स्वास्थ्य केवल व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं है बल्कि वैश्विक साझेदारी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिणाम है। आज जब विज्ञान और तकनीक ने चिकित्सा क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं, तब यह प्रश्न और अधिक प्रासंगिक हो जाता है कि क्या ये उपलब्धियां समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पा रही हैं? क्या हर महिला सुरक्षित मातृत्व का अनुभव कर पा रही है? क्या हर नवजात को जीवन की समान शुरुआत मिल रही है? यही वे मूल प्रश्न हैं, जिनका उत्तर इस वर्ष का विश्व स्वास्थ्य दिवस हमसे मांगता है।

स्वास्थ्य की अवधारणा अब केवल रोगों के उपचार तक सीमित नहीं रह गई है। यह एक समग्र दृष्टि है, जिसमें पोषण, स्वच्छता, मानसिक संतुलन, सुरक्षित पर्यावरण और सामाजिक समानता जैसे अनेक आयाम शामिल हैं। एक स्वस्थ समाज वह है, जहां एक गर्भवती महिला को समय पर देखभाल, सम्मान और पोषण मिले; जहां नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद आवश्यक चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो और जहां प्रत्येक नागरिक को जीवन के हर चरण में स्वास्थ्य सेवाओं की सहज उपलब्धता हो। यही कारण है कि आज स्वास्थ्य को वैश्विक स्तर पर एक मौलिक मानव अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है, भले ही इसकी वास्तविक उपलब्धता अब भी एक चुनौती बनी हुई है। वैश्विक परिदृश्य पर नजर डालें तो स्थिति मिश्रित दिखाई देती है। एक ओर चिकित्सा विज्ञान ने टीकाकरण, संक्रामक रोगों की रोकथाम, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं और आधुनिक सर्जरी के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, वहीं दूसरी ओर विश्व की बड़ी आबादी अब भी बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित है। विशेष रूप से मातृ और नवजात मृत्यु दर आज भी चिंता का विषय है। हर वर्ष लाखों महिलाएं गर्भावस्था और प्रसव के दौरान अपनी जान गंवाती हैं जबकि करोड़ों नवजात शिशु जीवन की पहली सांस लेने से पहले ही मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। यह स्थिति केवल संसाधनों की कमी का परिणाम नहीं बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं के असमान वितरण, जागरूकता की कमी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अभाव को भी दर्शाती है।

भारत के संदर्भ में यह चुनौती के साथ आशा की एक सशक्त कहानी भी प्रस्तुत करती है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है और एक ऐसा मॉडल विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं, जो समावेशी, किफायती और तकनीक-संचालित है। आयुष्मान भारत योजना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसे दुनिया के सबसे बड़े सरकारी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों में गिना जाता है। इस योजना के माध्यम से करोड़ों गरीब और वंचित परिवारों को निःशुल्क उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इसी प्रकार, मातृ और शिशु स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के लिए जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मिशन इंद्रधनुष और पोषण अभियान जैसी पहलें एक मजबूत आधार तैयार कर रही हैं। इन कार्यक्रमों ने न केवल संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दिया है बल्कि गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए आवश्यक टीकाकरण और पोषण सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सेविकाएं और एएनएम स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ बन चुकी हैं, जो घर-घर जाकर जागरूकता फैलाने और सेवाएं पहुंचाने का कार्य कर रही हैं। भारत का स्वास्थ्य मॉडल केवल योजनाओं तक सीमित नहीं है बल्कि यह विज्ञान और तकनीक के समन्वय पर आधारित है। डिजिटल हैल्थ मिशन, टेलीमेडिसिन सेवाएं, ई-हॉस्पिटल प्लेटफॉर्म और मोबाइल हैल्थ एप्लिकेशन ने स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ और पारदर्शी बनाया है। अब दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं, अपनी चिकित्सा रिपोर्ट ऑनलाइन देख सकते हैं और समय पर उपचार प्राप्त कर सकते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा विश्लेषण जैसी तकनीकें रोगों के प्रारंभिक निदान और रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और प्रभावशीलता दोनों में सुधार हो रहा है।

फिर भी, वैश्विक चुनौतियां कम नहीं हैं। बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, जीवनशैली में बदलाव और मानसिक तनाव जैसी समस्याएं स्वास्थ्य प्रणाली पर अतिरिक्त दबाव डाल रही हैं। गैर-संचारी रोगों (जैसे मधुमेह, हृदय रोग और कैंसर) का तेजी से बढ़ता प्रकोप यह संकेत देता है कि हमें केवल उपचार पर नहीं बल्कि रोकथाम और जागरूकता पर भी समान रूप से ध्यान देना होगा। इसके लिए आवश्यक है कि हम वैज्ञानिक सोच को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, स्वच्छता और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को अपनाएं। कोविड-19 महामारी ने यह स्पष्ट कर दिया कि स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश अब केवल एक विकल्प नहीं बल्कि अनिवार्यता है। इस संकट ने स्वास्थ्यकर्मियों की भूमिका को भी नए सिरे से परिभाषित किया, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर मानवता की सेवा की। यह अनुभव हमें यह सिखाता है कि एक मजबूत और लचीली स्वास्थ्य प्रणाली ही किसी भी आपदा का सामना कर सकती है। इसलिए सरकारों को स्वास्थ्य बजट में वृद्धि, चिकित्सा शिक्षा के विस्तार और अनुसंधान को प्रोत्साहन देने की दिशा में निरंतर प्रयास करना होगा।

मातृत्व और नवजात तो किसी भी समाज के भविष्य की नींव होते हैं। इसलिए हर महिला को यह अधिकार मिलना चाहिए कि वह सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से मातृत्व का अनुभव कर सके और हर नवजात को यह अवसर मिलना चाहिए कि वह स्वस्थ जीवन की शुरुआत कर सके। यह तभी संभव है, जब स्वास्थ्य प्रणाली समावेशी, सुलभ और संवेदनशील हो और उसमें विज्ञान तथा तकनीक का प्रभावी उपयोग किया जाए। विश्व स्वास्थ्य दिवस हमें यही संदेश देता है कि स्वास्थ्य का भविष्य केवल अस्पतालों और दवाइयों में नहीं बल्कि हमारी सोच, हमारी नीतियों और हमारे सामूहिक प्रयासों में निहित है। जब हम विज्ञान के साथ खड़े होकर, सहयोग की भावना से प्रेरित होकर और समानता के सिद्धांत को अपनाकर आगे बढ़ेंगे, तभी हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर पाएंगे, जहां स्वास्थ्य किसी विशेष वर्ग का विशेषाधिकार नहीं बल्कि हर व्यक्ति का सुनिश्चित अधिकार होगा। यही इस दिवस का सार है और यही वह दिशा है, जो हमें एक स्वस्थ, समृद्ध और आशापूर्ण भविष्य की ओर ले जाती है।

भाजपा ने जिला भाजपा कार्यालय पर ध्वजारोहण कर स्थापना दिवस मनाया

भाजपा पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संगठन बना : पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा

धार। भारतीय जनता पार्टी के 47वें स्थापना दिवस पर 6 अप्रैल को जिला भाजपा कार्यालय परिसर में भाजपा वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष महंत निलेश भारती, विधायक नीना वर्मा की गरिमामय उपस्थित व भाजपा भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ध्वजारोहण किया।

उपस्थित कार्यकर्ताओं एवं पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित कर सभी को स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं।

इस दौरान भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष प्रभु राठौड़ व दिलीप पटोदिया,भाजपा जिला महामंत्री देवेंद्र सोनोने, राकेश पटेल, भाजपा नेता डॉ. शरद विजयवर्गीय बसंतीलाल मामा जैन नगर मंडल अध्यक्ष विशाल निगम और जयराज देवड़ा मंचासीन रहे।

सर्व प्रथम भारत माता एवं पित्र पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय व डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्रों पर माल्यार्पण दीप प्रज्ज्वलित किया । भाजपा स्थापना दिवस पर प्रदेश कार्यालय से मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के संबोधन का सीधा प्रसारण को देखा और सुना। जिला कार्यालय पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की। अतिथियों द्वारा कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाकर इस गौरवपूर्ण दिवस की खुशी साझा की।

पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हम 6 अप्रैल 1980 से भाजपा परिवार की यात्रा का शुभारंभ कर आज हम पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संगठन बन गए हैं यह संगठन कार्यकर्ता आधारित संगठन है। आने वाले समय में हमें अनेक चुनौतियों का सामना करना है हम डिगे नहीं और मानसिक रूप से मजबूत बने। यह भाजपा कार्यालय प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए किसी मंदिर के समान है।

भाजपा 'अंत्योदय' और 'सशक्त भारत' के निर्माण हेतु निरंतर समर्पित हैं: महंत निलेश भारती

भाजपा जिलाध्यक्ष महंत निलेश भारती ने कहा कि आप सभी को विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के 47वें स्थापना दिवस की सभी का बधाई। इस गौरवशाली अवसर पर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पं. दीनदयाल उपाध्याय एवं श्रद्धेय अटल जी के चरणों में नमन किया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम 'अंत्योदय' और 'सशक्त भारत' के निर्माण हेतु निरंतर समर्पित हैं। यह ध्वज मात्र एक प्रतीक नहीं, बल्कि करोड़ों कार्यकर्ताओं के त्याग, तपस्या और 'राष्ट्र प्रथम' के संकल्प का प्रतिबिंब है। 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' को आत्मसात कर हम सभी अंत्योदय एवं आत्मनिर्भर भारत के पावन लक्ष्य की प्राप्ति के कर्तव्य पथ सतत् आगे बढ़ते रहेंगे। यह भाजपा कार्यालय प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए किसी मंदिर के समान है।

भाजपा जिला मीडिया प्रभारी संजय शर्मा ने बताया कि जिला कार्यालय पर स्थापना दिवस कार्यक्रम में पुर्व नगर पालिका अध्यक्ष ममता जोशी,जिला उपाध्यक्ष राखी राय, मोहित तातेड़, रंजीत भंडारी, मनीष प्रधान, नरेश राजपुरोहित अंकित भावसार, पूनम चंद फकीरा, दीपक बिडकर, एल्डरमैन प्रीति विशाल राठौर टोनी ठाकुर, सुरेश प्रजापत, सन्नी होड़ा पूर्व पार्षद हुकुम लश्करी लव प्रजापति देवेंद्र रावल, बादल मालवीय समेत महिला मोर्चा कार्यकर्ता उपस्थित रहें।

इंदौर ज्योतिष वास्तु सम्मेलन में ज्योतिष गुरु डॉ. अशोक शास्त्री ज्योतिष गौरव रत्न से सम्मानित

धार। श्री केवलराम धाम ज्योतिष संस्था इन्दौर द्वारा छटवां ज्योतिष वास्तु सम्मेलन अभिनव कला समाज भवन में आयोजित किया गया।

राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित प्रकाश गौड़ ने बताया कि देश विदेश के लगभग तीन सौ ज्योतिष विद्वान इस सम्मेलन में शामिल हुए जिसमें कामाख्या से संत श्री त्यागी बाबा, चित्तौड़ से ज्योतिष भवानी शंकर गौड़, एम के वाड्रा कलकत्ता से, तांत्रिक त्यागी बाबा कामाख्या धाम, पंडित नीरज शर्मा, पंडित पंकज शर्मा, डॉ. संतोष भार्गव, डॉ. संतोष वाधवानी, ज्योतिष गुरु डॉ. अशोक शास्त्री के साथ हरियाणा, पंजाब, उत्तरप्रदेश से विद्वान ज्योतिष शास्त्रियों ने जातकों की समस्या का निदान किया साथ ही अपने अपने ज्योतिष शोध प्रस्तुत किए।

कार्यक्रम अध्यक्ष श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर राम शंकर तिवारी महाराज , संरक्षक श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर प्रेमानंद महाराज ने की, इस अवसर पर मालवा क्षेत्र के प्रसिद्ध ज्योतिष गुरु डॉ. अशोक शास्त्री का ज्योतिष के साथ सामाजिक क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ज्योतिष गौरव रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कोषाध्यक्ष प्रीति गौड़ , प्रभारी पंडित संजय शर्मा, नीतु जोशी नीतु मितल,उपाध्यक्ष परमानंद पटेरिया, कार्यक्रम सचिव पंडित दिनेश शर्मा, कार्यक्रम महासचिव पंडित योगेश शर्मा, वरिष्ठ समाजसेवी जितेंद्र गुप्ता जीतू बाबा की गरिमामय उपस्थिति दर्ज रही। मंच संचालन ईशा जैन ने किया। आशीष शर्मा गौतम शर्मा हर्षित गौड़, दीप जैन अनीता शर्मा पुष्पलता जोशी अष्टांगिनी देवी अन्य सभी कार्यकारिणी सदस्यों ने व्यवस्था में सहयोग किया। जानकारी पंडित राजेश शर्मा ने दी ।

भाजपा का स्थापना दिवस वरिष्ठ भाजपा नेता चौधरी माधवसिंह के आतिथ्य में संपन्न हुआ

सोहागपुर। क्षेत्रीय विधायक विजयपालसिंह के सोहागपुर विधानसभा मुख्यालय कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस वरिष्ठ अधिवक्ता एवं भाजपा नेता चौधरी माधवसिंह के आतिथ्य में संपन्न हुआ। उल्लेखनीय है कि 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई थी। उक्त स्थापना दिवस मुख्य रूप से डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के राष्ट्रवादी विचारों व आदर्शों को समर्पित किया जाता है। भाजपा पार्टी की औपचारिक स्थापना अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में हुई थी। भाजपा का स्थापना दिवस डॉक्टर श्यामप्रसादमुखर्जी के राष्ट्रवाद एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद व अंत्योदय के सिद्धांतों को याद करते हुए मनाया जाता है। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। जिसमें आधार स्तंभ डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को भाजपा की नींव माना जाता है। 6 अप्रैल 1980 में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को भाजपा अध्यक्ष चुना गया था। उक्त स्थापना दिवस का यह दिन पार्टी के राष्ट्रवाद और राष्ट्र-सेवा के संकल्प को दोहराने के रूप में मनाया जाता है। विधायक कार्यालय पर आयोजित स्थापना दिवस पर वरिष्ठ अधिवक्ता एवं भाजपा नेता चौधरी माधवसिंह,नगर पंचायत परिषद उपाध्यक्ष आकाश रघुवंशी,मंडल अध्यक्ष अश्विनी सरोज,युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष नीरज यादव, तुलसीराम भल्लवी,पार्षद रविशंकर उइके, रूपेश रघुवंशी, युगल रघुवंशी कमलेश कहार तरुण पथरिया त्रिवेंद्र कुशवाहा आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। आभार ब्लाक भाजपा ने व्यक्त किया। इस अवसर पर ब्लाक भाजपा अध्यक्ष अश्विनी सरोज ने बताया कि सोहागपुर ब्लाक के समस्त बूथों पर भाजपा का स्थापना दिवस मनाया गया। उक्त आश्य की जानकारी ब्लाक भाजपा अध्यक्ष अश्विनी सरोज ने इस प्रतिनिधि को दी।

मां माचना समिति ने एल्डरमेनों का किया भव्य स्वागत

बैतूल। मां माचना समिति द्वारा रविवार को नगर पालिका के नवनियुक्त एल्डरमेनों का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर एल्डरमेन नितेश वर्मा, राजू सोनकपुरिया, रश्मी साहू, मन्नी अहलुवालिया, सावन्या शेषकर एवं कैलाश यादव ने मां माचना मंदिर पहुंचकर मचना मैया की विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर विकास वार्ड के पार्षद आनंद प्रजापति ने अपने उद्बोधन में कहा कि नगर के विकास और जनसेवा के लिए सभी जनप्रतिनिधियों को मिलकर कार्य करना होगा। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में हम सभी को संगठन को मजबूती देना होगा। उन्होंने कहा कि मां माचना का आशीर्वाद लेकर हम सभी शहर के सर्वांगीण विकास, स्वच्छता, पेयजल, सडक़ एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने नव-नियुक्त एल्डरमेनों को बधाई देते हुए विश्वास जताया कि वे जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए नगर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

गंज रेलवे अंडरब्रिज से 45 दिनों तक आवाजाही बंद, वाहन चालकों को फेरा लगाकर गंज पहुंचना पड़ रहा

ओवरब्रिज पर शिफ्ट हुआ ट्रैफिक, लग रहा बार-बार जाम

एस. द्विवेदी, बैतूल। तीसरी रेलवे लाइन और अंडरब्रिज की लंबाई बढ़ाने के कारण रेलवे ने 3 अप्रैल से 45 दिनों के लिए वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। अंडरब्रिज का रास्ता बंद होने से पूरा ट्रॉफिक सदर ओवरब्रिज पर शिफ्ट हो गया है, जिससे बार-बार ट्रैफिक जाम के हालात बन रहे है। हालांकि वाहन चालकों को परेशानी न हो, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने ओवरब्रिज से भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। भारी वाहन और बसें सोनाघाटी से होकर शहर में प्रवेश करेगी। लेकिन इसके बाद भी ओवरब्रिज पर ट्रॉफिक जाम की समस्या कम नहीं हुई है। हालात यह है कि सुबह और शाम के समय ओवरब्रिज के दोनों तरफ बार-बार जाम की स्थिति निर्मित हो रही है। बता दे कि मध्य रेल, बैतूल के निर्माण विभाग द्वारा जारी सूचना के अनुसार, बैतूल रेलवे स्टेशन के इटारसी छोर पर रेलवे किलोमीटर 850/41-43 के बीच स्थित अंडरपास में तीसरी लाइन के निर्माण के लिए इसकी लंबाई बढ़ाई जा रही है। इस निर्माण कार्य की कुल अवधि लगभग 45 दिन निर्धारित की गई है, जिसमें लगभग एक माह निर्माण कार्य और 15 दिन तराई के लिए रखे गए हैं।

सदर रेलवे गेट बंद होने से बढ़ी परेशानी

सदर का रेलवे गेट बंद होने के बाद आवाजाही के लिए गंज अंडरब्रिज और सदर ओवरब्रिज ही हैं। गंज अंडरब्रिज पर काम होने से केवल सदर ओवरब्रिज से ही वाहनों की आवाजाही होती है। यहां से मुलताई, आठनेर, बैतूलबाजार, भैंसदेही, चिचोली सहित अन्य जगहों से आने वाले वाहन सदर ओवरब्रिज होते ही शहर में आ रहे हैं। यदि एक भी मार्ग बंद हो जाता है तो ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाता है। सदर रेलवे गेट बंद होने का लोगों को जमकर विरोध किया था, लेकिन जनप्रतिनिधियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। रेलवे ने सदर अंडरब्रिज निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन आज तक यह स्वीकृत नहीं हुआ। जिले में केंद्रीय मंत्री होने के बाद भी सदर अंडरब्रिज की फाइल अटकी पड़ी है।

गंज आने के लिए 3 किमी का लगा रहे फेरा

45 दिनों तक अंडरब्रिज से आवाजाही बंद होने के कारण लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। इस अंडरब्रिज से रोजाना 10 हजार वाहन चालक गुजरते हैं। शहर में आने और शहर से बडोरा जाने के लिए वाहनों को अब 3 किलोमीटर का लंबा फेरा लगाना पड़ रहा है। वहीं रामनगर, गर्गकॉलोनी के बच्चों को भी प्रतिदिन 3 किलोमीटर का फेरा लगाना पड़ रहा है। इसके अलावा अंतिम संस्कार के लिए गंज मोक्षधाम जाने वाले लोगों और शव ले जाने वाले वाहनों को भी मार्ग परिवर्तन और जाम की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इधर ओवरब्रिज पर ट्रैफिक शिफ्ट होने से बार-बार जाम लग रहा है। यहीं स्थिति ओवरब्रिज सदर गेंदा चौक के पास भी है। यहां भी ट्रॉफिक जाम से वाहनों की लंबी-लंबी कतारे लग रही है।

ओवरब्रिज पर ट्रैफिक शिफ्ट होने से लग रहा जाम .....

गंज अंडरब्रिज बडोरा को गंज क्षेत्र से सीधे जोड़ता है। वर्तमान में बडोरा मंडी में उपज की बंपर आवक हो रही है। मंडी से उपज रेलवे माल गोदाम ले जाना पड़ता है, लेकिन भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित होने से वाहन चालकों को लगभग तीन किलोमीटर का फेरा लगाना पड़ रहा है। अधिकतर भारी वाहन और यात्री बसे कारगिल चौक, गेंदा चौक से सदर ओवरब्रिज से ही आना-जाना कर रहे है। जिससे गेंदा चौक सदर ओवरब्रिज और माचना ब्रिज पर दिन में कई बार जाम की स्थिति बन रही है और वाहन चालकों के साथ ही आम नागरिकों को भी परेशान हो रहे है। लेकिन जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे है। यदि यातायात व्यवस्था को लेकर ठोस और प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो आम नागरिकों की परेशानी और बढ़ सकती है।

ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने यह बना है प्लान...

(1) मुलताई की ओर से आने वाले मध्यम एवं भारी वाहन एलबी लॉन से सीधे फोरलेन का उपयोग कर भारत भारती से सोनघाटी फॉरेस्ट बैरियर होते हुए शहर में पहुंचेगे।

(2) इंदौर- चिचोली मार्ग से आने वाले बड़े वाहन तितली चौराहे से फोरलेन होते हुए भारत भारती एवं फॉरेस्ट बैरियर मार्ग से शहर में पहुंचेगे।

(3) शहर से बाहर जाने वाले वाले मध्यम एवं भारी वाहन गेंदा चौक से इटारसी रोड होते हुए फॉरेस्ट बैरियर मार्ग से भारत भारती की ओर निकलेंगे।

(4) बडोरा से आने वाले वाहन रामबोलो चौक (सदर ओवर ब्रिज चौराहा) से करबला होते हुए तितली चौराहे तक जाएंगे। इसके बाद फोरलेन से भारत भारती एवं फॉरेस्ट बैरियर होते हुए अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगे।

प्रभावित किसानों की हर संभव मदद की जाएगी : संभागायुक्त

संभागायुक्त ने मुलताई में ओलावृष्टि प्रभावित ग्रामों में फसल नुकसान का लिया जायजा

बैतूल। संभागायुक्त कृष्ण गोपाल तिवारी ने सोमवार को जिले के मुलताई क्षेत्र में ओलावृष्टि से प्रभावित ग्रामों का भ्रमण कर गेहूं, गोभी, चना, टमाटर सहित अन्य फसलों में हुई क्षति का जायजा लिया। इस दौरान कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, सीईओ जिला पंचायत अक्षत जैन, एसडीएम राजीव कहार, उप संचालक कृषि आनंद कुमार बड़ोनिया एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। संभागायुक्त श्री तिवारी ने ग्राम सेमझिरा, जमबाड़ी एवं धारणी का दौरा कर खेतों में पहुंचकर फसलों की वास्तविक स्थिति का आंकलन किया। उन्होंने किसानों से आत्मीय संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और नुकसान की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने बताया कि गठित सर्वे दलों द्वारा सूक्ष्मता से सर्वे कार्य किया जा रहा है, जो शीघ्र पूर्ण होगा। प्रभावित किसानों को राहत राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने मौके पर उपस्थित बीमा कंपनी के प्रतिनिधि को निर्देशित किया कि किसानों की फसल क्षति का समय पर

पोर्टल में पंजीयन सुनिश्चित किया जाए तथा बीमा दावा प्रक्रिया में किसी प्रकार की लापरवाही न हो। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सर्वे कार्य में कोई भी प्रभावित किसान न छूटे। संभागायुक्त ने ग्राम सेमझिरा में नल-जल योजना के क्रियान्वयन की भी जानकारी ली। ग्रामीणों द्वारा जल समस्या न होने की जानकारी देने पर उन्होंने जल स्त्रोतों के दीर्घकालीन प्रबंधन के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण- संभागायुक्त श्री तिवारी ने ग्राम सेमझिरा स्थित आंगनवाड़ी केंद्र का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सुपरवाइजर से बच्चों की उपस्थिति, पोषण आहार वितरण एवं केंद्र संचालन की जानकारी ली। उन्होंने निर्देशित किया कि गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों को नियमित रूप से पोषण आहार उपलब्ध कराया जाए तथा केंद्र निर्धारित दिवसों पर समय से संचालित हों।

एचपीवी टीकाकरण लक्ष्य शत-प्रतिशत पूर्ण करें- संभागायुक्त श्री तिवारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुलताई का निरीक्षण कर एचपीवी टीकाकरण की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने बालिकाओं एवं अभिभावकों को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए एचपीवी टीकाकरण के महत्व के बारे में जागरूक करने के निर्देश दिए। साथ ही, स्वास्थ्य विभाग को निर्धारित लक्ष्य शत-प्रतिशत पूर्ण करने के निर्देश दिए।

मुलताई पुलिस की बड़ी कार्रवाई

10 चोरी के दोपहिया वाहन बरामद, आरोपी गिरफ्तार, 6.60 लाख के वाहन जब्त

बैतूल। मुलताई पुलिस को दोपहिया वाहन चोरी के मामले में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 चोरी के दोपहिया वाहन (9 मोटरसाइकिल एवं 1 स्कूटी) बरामद किए हैं, जिनकी कुल अनुमानित कीमत लगभग 6 लाख 60 हजार बताई जा रही है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, थाना मुलताई पुलिस को देहात भ्रमण के दौरान एक विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम लेंडागोंदी निवासी पंकज पंवार अपने खेत स्थित भैंस के बाड़े में चोरी की कई मोटर साइकिलें छिपाकर रखे हुए है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने पंचों के साथ मौके पर दबिश दी। दबिश के दौरान एक व्यक्ति पुलिस

को देखकर भागने का प्रयास करने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम पंकज पिता हीराचंद पंवार (31 वर्ष), निवासी लेंडागोंदी, थाना मुलताई, जिला बैतूल बताया।

तलाशी में 10 वाहन बरामद- आरोपी के भैंस बाड़े की तलाशी लेने पर कुल 10 दोपहिया वाहन बरामद किए गए, जिनमें 9 मोटरसाइकिल और 1 स्कूटी शामिल है। बरामद वाहनों की कुल अनुमानित कीमत 6,60,000 है। आरोपी किसी भी वाहन के वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका और न ही संतोषजनक जवाब दे पाया। प्रथम दृष्टया मामला अपराध का पाए जाने पर आरोपी के विरुद्ध धारा 35(1)(ड) बी.एन.एस.एस. एवं 305(बी) बी.एन.एस. के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

संकट मोचन के दरबार में 13 मुस्लिम कलाकार भी लगाएंगे हाजिरी

संकट मोचन संगीत समारोह-2

राजेन्द्र शर्मा

(लेखक संगीत समीक्षक और पूर्व शासकीय अधिकारी हैं)

संकट मोचन संगीत समारोह के 103वें आयोजन की घोषणा के समय महंत बिशम्भजर नाथ मिश्र ने कहा कि देश में एक मंदिर ऐसा भी रहने दिया जाए, जहां सब धर्मों और विचारों के लोगों को आने की अनुमति हो। उल्लेखनीय है कि 103वें आयोजन में 13 मुस्लिम कलाकार संकट मोचन के दरबार में अपनी हाजिरी लगाएंगे।

1923 से अनवरत हो रहे देश के सबसे प्राचीन संगीत समारोह में 2005 तक मुस्लिम कलाकारों को नहीं बुलाया जाता था, लेकिन 2006 में हुई एक घटना का सकारात्मक जवाब देने के लिए तत्कालीन मंहत वीरभद्र मिश्र ने उसी साल से मुस्लिाम कलाकारों के लिए समारोह के द्वार खोल दिए।

महंत वीरभद्र मिश्र के इस अप्रत्याशित निर्णय की पृष्ठभूमि संकट मोचन मंदिर में सीरियल बम ब्लास्ट का होना रहा। किस्सा साल 2006 के माह मार्च का है। संगीत समारोह के मुख्य कर्ताधर्ता महंत वीरभद्र मिश्र अगले माह होने वाले 83वें संकट मोचन समारोह की तैयारियों में जुटे थे। 7 मार्च 2006 को एकाएक वाराणसी में कैंट स्टेशन और संकट मोचन मंदिर सीरियल बम ब्लास्ट से कांप गया। इस आतंकी हमले के बाद क्या हिंदू और क्या मुसलमान सभी आशंकित कि गंगा-जमुनी तहजीब से लबालब वाराणसी का सौहार्द्र बचेगा भी या नहीं। ऐसे कठिन समय में महंत वीरभद्र मिश्र ने ऐतिहासिक फैसला लिया कि समारोह के 83वें आयोजन में मुस्लिम कलाकारों को भी मंच प्रदान किया जाएगा। संभवतः धार्मिक रूप से इस महत्वपूर्ण मंदिर में मुस्लिम कलाकारों की हिस्सेदारी पर मनाही रही होगी। लिहाजा महंत जी फैसले का कट्टरपंथी लोगों ने धीमे स्वर में

विरोध भी किया, परन्तु महंतजी टस से मस नहीं हुए और 83वें संकट मोचन संगीत समारोह में भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के भांजे मुमताज खां ने शहनाई बजाकर अपनी हाजिरी लगायी और संकट मोचन संगीत समारोह में शिरकत करने वाले पहले मुस्लिम कलाकार बनें। इसके बाद गजल सम्राट गुलाम अली, तलत अजीज, बॉलीवुड गायक जावेद अली, कमाल साबरी, उस्ताद निशात खां, उस्ताद मोइनुद्दीन खां, उस्ताद राशिद खान, अरमान खान, बिलाल खान, उस्ताद मुराद अली, शाकिर खान, शमीउल्लाह खान, उस्ताद शाहिद परवेज खान उस्ताद अकरम खां, बिलाल खां आदि कलाकार हनुमत प्रभु के पांव पखार चुके हैं।

संकट मोचन संगीत समारोह के तीसरे और वर्तमान संयोजक महंत विशम्भर नाथ मिश्र ने अपने बाबा और पिता के रास्ते पर चलते हुए विदेशी कलाकारों के लिए भी मंदिर के द्वार खोलने का अद्भुत काम किया है। इसकी शुरुआत 2014 में पाकिस्तान के फनकार गुलाम अली ने यहां हाजिरी लगाकर की। गुलाम अली दो बार इस समारोह में अपनी हाजिरी लगा चुके हैं। हालांकि तब भी कट्टरपंथियों ने इसका विरोध किया था, लेकिन गुलाम अली ने अपनी प्रस्तुति देकर सबको अपना मुरीद बना लिया।

साल 2024 में संकट मोचन संगीत समारोह के 101वें आयोजन में उस्ताद राशिद खान वर्षो की तरह अपनी हाजिरी लगाना चाहते थे, किन्तु 9 जनवरी 2024 को कैंसर से जूझते हुए इस दुनिया से रुखस्त हो गये। बेहद संवेदनशील महंत बिशम्भर नाथ मिश्र ने उसी दिन फैसला कर लिया था कि उस्ताद राशिद खान की जगह उनका अंश अरमान खान संकट मोचन के दरबार में आपकी इच्छा को पूरा करेगा। 101वें आयोजन में बीस वर्षीय पुत्र अरमान खान की श्रोताओं और महंत बिशम्भकर नाथ मिश्र ने जिस तरह हौसला अफजाई की, उसे देख अरमान खान, उनकी मां और बहन भाव विह्वल हो उठे। महंत बिशम्भर नाथ मिश्र ने कहा कि राशिद खान साहब कहीं नहीं गए हैं, वो अरमान खान के रुप में हमारे बीच हैं और हम सब इस बच्चे के कस्टोपडियन है, उस्ताद राशिद खान जिस ऊंचाइयों तक पहुंचे, उस मुकाम तक अरमान को ले जाने की जिम्मेदारी हम सब की है।

महंत बिशम्भर नाथ मिश्र कहते हैं कि संकट मोचन संगीत समारोह का प्रारूप संगीत और संस्कृति की पूरी अवधारणा को धार्मिक होने से बचाता है। संगीत समारोह और गंगा में एकरूपता है। जैसे गंगा सभी के लिए है, वैसे ही संकट मोचन का मंच भी सभी के लिए है। ये सभी के लिए जीवन के अविकल और निर्विवाद आधार हैं।

'मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं'

मंच पर अधिकारियों से ज्योतिरादित्य सिंधिया थैले में रखवाने लगे आवेदन, कहा- यह सोना है

अशोकनगर (नप्र)। केंद्रीय मंत्री और गुना-शिवपुरी के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दिनों अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं। उनकी सक्रियता कई वजहों से चर्चा में है। अशोकनगर जिले के ईसागढ़ में जनसुनवाई आयोजित की गई थी। इस दौरान शिकायती आवेदनों का ढेर लग गया है। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अधिकारियों को इसे सहेजना सिखाया है।

यह कागज का टुकड़ा नहीं, मेरे लिए सोना है..- ईसागढ़ क्षेत्र में जनसुनवाई के दौरान सिंधिया ने मंच पर ही कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों की क्लास लगा दी। सख्त लहजे में अधिकारियों से कहा कि यह कागज के टुकड़े नहीं ,यह मेरे लिए सोना है। इतना ही नहीं सिंधिया स्वयं खड़े होकर एक-एक आवेदन अशोकनगर कलेक्टर से थैले में रखवाएं।

3 घंटे तक चली जनसुनवाई- दरअसल, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने चार दिवसीय दौरे के अंतिम दिन ईसागढ़ पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने जनसुनवाई में आमजन की समस्याएं सुनी। तीन घंटे चली इस जनसुनवाई में सिंधिया ने 950 आवेदन में से 280 मामलों में तुरंत निराकरण भी करवाया। जनसुनवाई समाप्त होने के बाद अभी तक आए आवेदन को सुरक्षित रखने को लेकर सिंधिया ने अधिकारियों की मंच पर क्लास ले ली। सिंधिया ने अशोक नगर कलेक्टर एवं संयुक्त कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों से स्वयं खड़े होकर आवेदन सही ढंग से जमवाया। फिर उन्हें सुरक्षित थैले में भी रखवाया है।

इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अधिकारियों से कहा कि जब मैं ठीक ढंग से रख सकता हूं तो प्रशासन क्यों नहीं। जैसे मैने किया है वैसे ही चाहिए मुझे...। सीधे-सीधे होना चाहिए एक-एक आवेदन।

डैम में नहाने गए थे 6 दोस्त...3 की डूबकर मौत

तैरना नहीं आता था, मस्ती करते वक्त गहराई में समाए, एसडीआरएफ ने निकाले शव

अशोकनगर (नप्र)। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में सोमवार दोपहर 3 नाबालिग दोस्तों की डैम में डूबने से मौत हो गई। तीनों मौज-मस्ती के लिए डैम गए थे, लेकिन कुछ ही पलों में गहराई में समा गए। मामला नई सराय थाना क्षेत्र का है।

जानकारी के मुताबिक, मृतकों की पहचान मयंक (16) पिता अवधेश रघुवंशी, देव (16) पिता राकेश रघुवंशी और ओम (15) पिता सतीश रघुवंशी के रूप में की गई है। तीनों अजलेश्वर गांव के हैं।

6 दोस्त नहाने गए थे, इनमें 3 डूब गए- परिजनों ने बताया कि 6 लड़के रोज की तरह पास के डैम में नहाने पहुंचे थे। शुरुआत में सभी नहा रहे थे, लेकिन कुछ ही देर में तीन लड़के गहराई की ओर बढ़ गए।बताया जा रहा है कि तीनों को तैरना नहीं आता था। अचानक गहराई बढ़ने से वे संतुलन खो बैठे और डूबने लगे। दोस्तों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा गहराई के कारण वे डर गए और बाहर निकल आए।

दोस्तों ने सूचना दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी- घटना के बाद अन्य लड़के घबराकर गांव भागे और परिजनों को सूचना दी। देखते ही देखते गांव के लोग मौके पर जुट गए। ग्रामीणों ने तलाश शुरू की, लेकिन गहराई और सीमित संसाधनों के कारण सफल नहीं हो सके।

एसडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू किया- ग्रामीणों ने नई सराय थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची। स्थिति की गंभीरता देखते हुए एसडीआरएफ टीम को बुलाया गया। कुछ देर बाद टीम पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया।

टीम ने मशक्कत के बाद डैम से तीनों किशोरों के शव निकाले। पूरे गांव में मातम छा गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में डूबने से मौत की पुष्टि हुई है।

महिला को पीटा, साड़ी फाड़ी, गैंगरेप की कोशिश

धार में जमीन विवाद में 5 लोगों ने हमला किया, आरोपियों में तीन महिलाएं शामिल

धामनोद (धार) (नप्र)। धार जिले में एक महिला ने 5 लोगों पर पीटने और गैंगरेप की कोशिश का आरोप लगाया है। आरोपियों में तीन महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की है।

मामला धामनोद थाना क्षेत्र में रविवार दोपहर करीब साढ़े 12 बजे का है। घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें 38 वर्षीय पीड़िता पुलिस और कुछ लोगों के साथ खड़ी दिख रही है। उसके शरीर पर बहुत कम कपड़े हैं।

जेसीबी से बाउंड्री वॉल के खंभे तोड़े- पीड़ित महिला ने पुलिस को बताया- हमारे खेत से आरोपी असुबाई की जमीन लगी है। रविवार को असुबाई, उसके बेटे अमित और गोपाल जेसीबी से जमीन समतल कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने घर के पीछे बनी बाउंड्री वॉल के खंभे तोड़ दिए।

शिकायत करने पर आरोपी बहस करने लगे और लात-घूंसों से मारपीट की। कुछ देर में असुबाई की बेटियां अतिना और हेमा भी मौके पर पहुंच गईं। सभी ने मिलकर मुझे पकड़ा और खींचकर कमरे में ले गए। वहां मारपीट की। मेरी साड़ी उतार दी। इसके बाद अमित और गोपाल ने मेरे साथ छेड़खानी की और गैंगरेप की कोशिश की। मैं धक्का देकर कमरे से बाहर भागी। बाहर चिल्लाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। किसी ने पुलिस को फोन किया। डायल 112 मौके पर पहुंची और हमें थाने लेकर गई।

सभी आरोपी फरार, पुलिस तलाश में जुटी- धामनोद पुलिस ने पीड़िता के आवेदन पर पांचों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की है। फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं। उनकी तलाश में पुलिस टीमें छापे मार रही हैं।धामनोद सिविल अस्पताल की डॉ. रश्मि सोलंकी ने बताया कि मारपीट के मामले में महिला को चेकअप के लिए लाया गया था। उसके शरीर पर मामूली चोटें और खरोंच के निशान हैं।

शादीशुदा महिला को प्रेमी के साथ रहने की मिली अनुमति

हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच का फैसला, पति से 21 साल छोटी थी पत्नी

ग्वालियर (नप्र)। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एक शादीशुदा युवती को उसके प्रेमी के साथ रहने की अनुमति दी है। बेंच ने हेबियस कॉर्पस (बंदी प्रत्यक्षीकरण) के एक मामले में सुनवाई करते हुए युवती को उसके प्रेमी के साथ रहने की आजादी दी। युवती ने कोर्ट में कहा था कि उसके पति की उम्र 40 साल है। अपने से 21 साल बड़े पति के साथ उसका वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं है। उसके अपनी मर्जी से प्रेमी के साथ रहने की बात कही थी।

कोर्ट ने युवती की स्वतंत्र इच्छा को प्राथमिकता देते हुए उसे जाने की अनुमति दी और 6 महीने के लिए शौर्या दीदी के रूप में निगरानी व्यवस्था भी तय की। साथ ही निर्देश दिए गए कि औपचारिकताएं पूरी कर युवती को वन स्टॉप सेंटर से मुक्त किया जाए।

पति ने लगाई थी याचिका

दरअसल युवती के पति ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसकी पत्नी को अनुज कुमार नामक युवक ने अवैध तरीके से अपने पास रखा है। सुनवाई के दौरान जब महिला को जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस पुष्पेंद्र यादव की खंडपीठ में पेश किया गया तो कहानी में नया मोड़ सामने आया।

कोर्ट ने क्या कहा

अदालत ने अपने आदेश में कहा चूंकि महिला बालिग थी और अपनी मर्जी से काम कर रही थी, इसलिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का मकसद पूरा हो चुका था। उसे उसके पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के साथ रहने की अनुमति देने से पहले, जजों ने निर्देश दिया कि महिला को छह महीने के लिए राज्य के शौर्य दीदी फ्रेमवर्क के तहत रखा जाए।

युवती ने कोर्ट में क्या कहा

युवती ने हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच को बताया कि वह बालिग है और अपनी मर्जी से प्रेमी के साथ रह रही है। युवती ने कहा कि उसके और पति के बीच उम्र का अंतर बहुत ज्यादा है। युवती ने कहा कि उसकी उम्र 19 साल है जबकि उसके पति की उम्र 40 साल है। उम्र के इस फासले के कारण वैवाहिक जीवन में सामंजस्य नहीं है। उसने कोर्ट को यह भी बताया कि पति के घर में उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था। युवती ने अपने माता-पिता के घर में भी रहने से इंकार कर दिया। उसने कहा कि वह अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती है।

काउंसलिंग के बाद भी नहीं बदला फैसला

कोर्ट के निर्देश पर युवती की काउंसलिंग कराई गई ताकि वह अपने परिवार के साथ रहे सके। लेकिन काउंसलिंग के बाद भी उसने अपने पति की जगह प्रेमी के साथ रहने की बात कही। वहीं, कोर्ट में युवती के प्रेमी ने भी कहा कि वह युवती की पूरी देखभाल करेगा किसी तरह की प्रताड़ना नहीं देगा। जिसके बाद कोर्ट ने पति की याचिका को खारिज करते हुए युवती को उसके प्रेमी के साथ रहने की इजाजत दे दी। जानकारी के मुताबिक, युवती की शादी एक साल पहले हुई थी।

युवक को चाकू से गोदा,पेट की आंतें तक निकल आईं

मंदसौर में दौड़ा-दौड़ाकर पीटा ; एक महीने से चल रहा था विवाद

मंदसौर (नप्र)। मंदसौर के गांधी चौराहा क्षेत्र में रविवार देर रात करीब 11 बजे चाकूबाजी हुई। नरसिंहपुरा निवासी अरुण (19) पिता नानावटी बरगुण्डा पर दो युवकों ने चाकू से हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हुआ था। इलाज के दौरान सोमवार सुबह उसकी मौत हो गई। घटना के बाद अरुण पिता नानावटी बरगुण्डा को जिला चिकित्सालय ले जाया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया, लेकिन उसके पेट के कई अंग बाहर आ गए थे, जिससे हालत चिंताजनक थी। इसलिए उसे बेहतर इलाज के लिए रतलाम मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

महुआ से भरा थैला लेकर चला गया बाघ

युवक की पूरी मेहनत पर फिरा पानी, चुपचाप खड़ा होकर देखता रहा

उमरिया (नप्र)। विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में आए दिन कोई न कोई अजीबो-गरीब घटना होती ही रहती है। अब एक नया और लोगों को रोमांचित करने वाला विडियो सामने आया है। जिसमें साफ नजर आ रहा है कि ग्रामीण महुआ बीन रहा था। उसी समय उसको किसी वन्य जीव की आहट सुनाई दी तो वो सतर्क होकर दूर खड़ा हो गया। इतने में झाड़ियों के बीच से बाघ निकला और ग्रामीण द्वारा बीने गए महुए के थैले को अपने मुंह में दबा कर जंगल की तरफ चला गया, ग्रामीण बेचारा देखता ही रह गया।

महुआ बीन रहे ग्रामीण के सामने पहुंच गया बाघ- पूरी घटना जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पनपथा बफर क्षेत्र के बंदरचुई इलाके से सामने आई है। जंगल में महुआ बीन रहे एक ग्रामीण के पास अचानक बाघ पहुंच गया। ग्रामीण पेड़ के नीचे महुआ बीनकर थैले में भरकर रखा हुआ था, तभी बाघ वहां आकर पहले कुछ देर पेड़ के नीचे बैठा रहा। इसके बाद उसने महुआ से भरा थैला मुंह में दबाया और जंगल की ओर चला गया।

चुपचाप खड़ा होकर देखता रहा युवक- घटना के दौरान ग्रामीण कुछ दूरी पर खड़ा होकर बाघ को देखता रहा। पूरे घटनाक्रम का वीडियो सामने आया है, जो लोगों को रोमांचित कर रहा है। बताया जा रहा है कि यह क्षेत्र बफर एरिया में आता है, जहां पर्यटकों का भी आना-जाना लगा रहता है। वीडियो सामने आने के बाद वन अमले ने क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है। प्रतीक श्रीवास्तव, रेंजर ने कहा वीडियो की जानकारी मिलने के बाद जंगल में सर्चिंग बढ़ा दी गई है। साथ ही महुआ बीनने के लिए जंगल जाने वाले ग्रामीणों को सतर्क रहने और समूह में जाने की सलाह दी जा रही है।

पनपथा बफर क्षेत्र- गौरतलब है कि वीडियो में दिख रहा है कि एक तरफ युवक खड़ा है। वहीं, थोड़ी दूरी पर्यटकों की जिप्सी है। सभी लोग इस रोमांचक पल को कैमरे में कैद कर रहे थे। बाघ महुआ से भरा थैला लेकर चुपचाप वहां से चला गया।

क्या महाकुंभ आज भी है आपके मन में?

नितिन वैद्य

भारत की संस्कृति में यदि कोई सबसे विराट और अद्भुत उत्सव है, तो वह है महाकुंभ। यह केवल स्नान का मेला नहीं, बल्कि सनातन आत्मा का महासंगम है, जहाँ श्रद्धा, विश्वास और भक्ति एक साथ उमड़ पड़ते हैं।

मैं स्वयं उस पावन क्षण का साक्षी रहा हूँ। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर मैंने भी पवित्र डुबकी लगाई। जब शरीर गंगा-यमुना और अदृश्य सरस्वती की धारा में डूबा, तो लगा मानो आत्मा भी शुद्ध होकर नवजीवन पा रही हो।

कुंभ का आयोजन हर 12 वर्ष में होता है और 144 वर्षों में एक बार 'महाकुंभ' का योग आता है। ऋग्वेद, अथर्ववेद और पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार, अमृत मंथन के समय जो अमृतकलश छलका था, उसकी बूँदें चार स्थलों पर गिरीं–प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। तभी से यह तीर्थस्थल महाकुंभ का धाम बने।

प्रयागराज के उस महासागर समान मेले में मैंने देखा–कोई भेदभाव नहीं।

न कोई जात, न कोई पात

न गरीब, न अमीर।

न बड़ा, न छोटा।

'सभी माँ गंगा की गोद में उतरकर समान भाव से स्नान कर रहे थे।'

मुझे स्मरण है–मैंने वहाँ उन महाधनवानों को भी देखा, जिनके बंगलों के स्नानगृह में एक बाल दिख जाए तो पूरा स्नानगृह पुनः धुलवाया जाता है। किंतु गंगा जी की धारा में वही लोग बिना किसी जाति सम्प्रयदाय के, साधुओं और सामान्य जनों के साथ एक ही जल में स्नान कर रहे थे। *यही है सनातन संस्कृति की वास्तविक शक्ति–समता और एकता का संदेश।

विश्व के अनेक देश हैं, जिनकी पूरी जनसंख्या भी 63 करोड़ तक नहीं पहुँचती। किंतु प्रयागराज के उस सीमित क्षेत्र में इतने लोग एकत्र हुए और फिर भी व्यवस्था, श्रद्धा और शांति बनी रही। 'यह किसी चमत्कार से कम नहीं। यह था सनातन धर्म का अद्वितीय वैभव।'

महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारत की आत्मा का उत्सव है। प्रयागराज के घाटों पर साधु-संतों की अखाड़ों की शोभायात्राएँ, मंत्रोच्चारण, दीपमालाएँ, और आध्यात्मिक वाणी मन को द्रवित कर देती है। हर घाट पर भक्ति का सागर उमड़ता है।

गंगा जी की धारा में जब मैंने डुबकी लगाई, तो लगा जैसे समस्त भेदभाव उस जल में विलीन हो गया हो।

'वह भाव आज भी मेरे हृदय में जीवित हैकि सनातन हमें जोड़ता है बाँधता नहीं।'

प्रयागराज का महाकुंभ इस सत्य का जीता-जागता प्रमाण है। महाकुंभ केवल तीर्थस्नान नहीं, बल्कि यह वह दिव्य क्षण है जब हमें याद दिलाया जाता है कि हम सब एक ही मानवता के धारा-पुत्र हैं। गंगा का जल हमें यह सिखाता है कि जैसे उसकी लहरों में कोई भेदभाव नहीं, वैसे ही हमारे हृदय में भी किसी प्रकार का भेदभाव न हो।

महाकुंभ का सबसे बड़ा संदेश यही है–

'सनातन की शक्ति हमें जोड़ती है, बाँधती नहीं।'

'गंगा की गोद में सभी समान हैं, और यही है भारत की सच्ची आत्मा।'

श्री कृष्ण शरणम मम

गुना के स्कूल में मधुमक्खियों ने बोला हमला

प्रार्थना कर रहे दर्जनों बच्चे और शिक्षक घायल, दो घंटे तक शिक्षा विभाग ने की जांच

गुना (नप्र)। शहर के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान वंदना कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में सोमवार की सुबह उस समय चीख-पुकार मच गई, जब प्रार्थना सभा से ठीक पहले मधुमक्खियों के एक झुंड ने अचानक हमला कर दिया। इस अप्रत्याशित घटना में लगभग तीन दर्जन से अधिक छात्र-छात्राएं, अभिभावक और स्कूल स्टाफ घायल हो गए।

स्कूल परिसर में अफरा-तफरी का माहौल

मधुमक्खियों के हमले से स्कूल परिसर में करीब आधे घंटे तक अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बना रहा। इधर घटना पर स्कूल प्रबंधन ने बोलना तो दूर स्कूल परिसर में मीडिया को घुसने तक नहीं दिया। वहीं, मौके पर पहुंची शिक्षा विभाग की टीम ने लगभग दो घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के गरिमा टोपे के अनुसार आधा दर्जन से अधिक बच्चे एवं शिक्षकों को मधुमक्खियों ने काटा है। जबकि परिजनों का कहना है लगभग दो दर्जन बच्चे और एक दर्जन से अधिक अभिभावक घायल हैं।

राइट क्लिक

विस चुनाव: महिलाओं को नकद रेवड़ी निर्णायक साबित हो सकती है

अजय बोकिल

लेखक सुबह सवेरे के कार्यकारी प्रधान संपादक हैं।
संपर्क-
9893699939
ajaybokil@gmail.com

देश के पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों में से तीन पुदुच्चेरी, असम और केरल विस के लिए 9 अप्रैल को मतदान होने जा रहा है। ऐसे में इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि कौन-सा मुद्दा मतदाता को प्रभावित करेगा? कौन-सा फैक्टर गेमचेंजर हो सकता है? ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है तो सत्ता परिवर्तन अथवा सत्ता में वापसी करा सकती है? गहराई से देखें तो बाकी मुद्दे एक तरफ नकदी रेवड़ी एक तरफ। हाल के कुछ वर्षों में सत्तारूढ़ दलों के हाथ यह ऐसा नुस्खा हाथ लग गया है, जिसके चलते राज्यों में किसी भी सत्तासीन पार्टी को उखाड़ फेंकना विपक्षी दलों के लिए टेढ़ी खीर होता जा रहा है। इस रेवड़ी कल्चर की डिजाइन भी उन महिलाओं को ध्यान में रख कर की गई हैं, जिनकी संख्या कुल वोटरों का करीब आधी है और जिनका समर्थन किसी भी पार्टी को सत्ता में लौटा या सत्ता से हटा सकता है। इसी दशक की बात करें तो इसकी शुरूआत सबसे पहले ममता बैनर्जी ने पश्चिम बंगाल के चुनाव में 2021 में 'लक्ष्मीर भंडार' नामक योजना से की थी, जिसके तहत हर महिला को 500 रू. प्रति माह दिए जाते थे। इसके बाद बंगाल की महिलाएं मोटे तौर ममता दीदी के साथ ही खड़ी रही हैं। हर चुनाव में इस राशि में 500 रू. की वृद्धि की जाती है। अब यह 1500 रू. है और इसमें भी एससी/एसटी को 1700 रू. हर माह मिलते हैं। इसका लाभ राज्य की करीब ढाई करोड़ महिला वोटरों को मिल रहा है। इस नकद रेवड़ी की चुनावी ताकत को भांप कर मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा ने सत्ता में आने पर इसकी राशि 3 हजार रू. प्रति माह करने का चुनावी वादा किया है। इसका राज्य की महिलाओं पर कितना असर होगा, यह तो नतीजों से पता चलेगा।

इस शर्तिया नुस्खे की शुरूआत तो ममता दी दी ने की थी, लेकिन 2023 में मध्यप्रदेश में मामा शिवराज ने इसे एक व्यवस्थित रूप दिया। इसके चलते मप्र में भाजपा भारी बहुमत से पांचवी बार सत्ता में लौटी तो अन्य राज्यों की सरकारों ने भी इस नकदी नुस्खे को अपनी गांठ में बांध लिया। यानी 2021 से अब तक देश में कुल 15 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें 6 राज्यों में सत्तारूढ़ दल सत्ता में लौटे। फर्क ऐसी योजना के नामों और राशि जरूर रहा है। लेकिन भुगतान का तरीका वही सीधे खातों में ऑन लाइन भेजने का है। गरीब और निम्न वर्ग की महिलाओंके लिए छोटी-सी लगने वाली यह रकम भी बहुत मायने रखती है। उनके वोट की प्राथमिकता तय करने में इस रकम का निर्णायक रोल होता है। इसके आगे विचारधारा, अन्य सुख-सुविधाएं और विकास आदि की बाते गौण हैं। हाथ खर्च के लिए बिना किसी मेहनत के मिलने वाले दो पैसे भी भगवान मिलने जैसे हैं। पिछले दिनों हुए विधानसभा चुनावों में केवल आंध्र प्रदेश और दिल्ली प्रदेश के विस चुनावों को अपवाद जहां, महिलाओंको नकदी बांटने का फार्मूला सत्तारूढ़ दल को चुनाव नहीं जितवा पाया। वहां राज कर रही पार्टी के बाकी शायद पाप नकदी खैरात पर भारी पड़े। ये राज्य हैं-आंध्र प्रदेश, जहां 2020 में सत्ता में आई वायएसआर कांग्रेस ने महिलाओं को वायएसआर चेयुथा नामक योजना के तहत एकमुश्त 18 हजार 759 रूपए देना शुरू किया था, लेकिन 2024 का विधानसभा चुनाव वो बुरी तरह हारे। ऐसा लगता है कि मासिक नकदी महिलाओं को ज्यादा फायदेमंद लगती है, बजाए कोई धंधा करने के लिए दी गई एक मुश्त रकम के। इसी तरह दिल्ली में दो बार से विधानसभा चुनाव जीत रही आम आदमी पार्टी तीसरी बार सत्ता में नहीं लौट सकी, क्योंकि उसने दिल्ली की महिलाओं को 'महिला समृद्धि योजना' के तहत प्रतिमाह 2500 रू. देने का वादा तो किया, लेकिन देना शुरू नहीं किया। हालांकि दे तो अब वहां की बीजेपी सरकार भी नहीं रही है। लिहाजा अगला चुनाव उसके लिए भी कठिन साबित हो सकता है। जबकि मप्र में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1250 रू, तेलंगाना में महालक्ष्मी योजना के अंतर्गत 2500 रू, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में 1500 रू, कर्नाटक में गृहलक्ष्मी योजना के तहत 2000 रू, बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत एक मुश्त 10 हजार रू., तमिलनाडु में कलैनार मगालिर उरिमई थोगई (महिला अधिकार अनुदान) के तहत 1 हजार रू., झारखंड में सीएम मइया योजना में 2500 रू, ओडिशा में सुभद्रा योजना 833 रू., छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के तहत 1 हजार रू. असम में अरूणोदय योजना के अंतर्गत 1250 रू. हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 2100 रू तथा हिमाचल प्रदेश में इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना में 1500 रू. प्रति माह महिलाओं को दिए जा रहे हैं। केरल में सीधे तौर पर नकदी देने की योजना नहीं है, लेकिन वहां कम्युनिस्टों ने तीन दशक पहले कुटुंबश्री योजना शुरू की थी, जिसकी आज 46 लाख से ज्यादा लाभार्थी दीदियां हैं। योजना के तहत सरकार महिलाओं को छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता देती है। ये वाम दलों की ताकत हैं। इसी तरह पुदुच्चेरी में होने वाले चुनाव में भी नकदी रेवड़ी की चर्चा नहीं है। लेकिन महिलाओं को सीधे नकदी के दम पर महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, मप्र, झारखंड, असम, और हरियाणा में सरकारें तमाम एंटी इनकम्बेंसी को मात देकर सत्ता में लौटी हैं और तेलंगाना,कर्नाटक, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और हिमाचल की सरकारें इसे आगामी विस चुनावों में आजमाएंगी। इसका अर्थ यह नहीं कि सत्तारूढ़ दलों की सरकार में वापसी का यही एक कारण है, लेकिन यह महत्वपूर्ण कारण जरूर है। जैसे-जैसे महिलाओंका वोटिंग प्रतिशत बढ़ रहा है, वैसे-वैसे इस योजना का राजनीतिक फलित भी सुखकर साबित हो रहा है।

जिन पांच राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उनमें केन्द्र शासित राज्य पुदुच्चेरी को छोड़ दें तो बाकी चार में नकदी रेवड़ी के इर्दगिर्द ही राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्र और चुनावी व्यूहरचना दिखाई देती है। मसलन केरल में वाम दलों के गठबंधन एलडीएफ ने महिलाओंको सीधे नकदी का तो कोई वादा नहीं किया है, लेकिन मुख्य विपक्षी कांग्रेस नीत यूडीएफ ने इंदिरा गारंटी के तहत महिलाओं तो 3000 रू पेशंन तथा फ्री बस पास की पेशकश की है। वहीं भाजपानीत एनडीए भी 3 हजार रू. पेंशन देने की वकालत कर रहा है। मतदाता किस पर भरोसा करेगा, यह नतीजे बताएंगे।

इसी तरह असम में महिलाओं को नकदी देने की अरूणोदय योजना पहले से लागू है। लेकिन वहां विपक्षी कांग्रेस ने महिलाओं को कारोबार के लिए साल में 50 हजार रुपये देने और हर परिवार को 25 लाख रुपये का कैशलेस हेल्थ कवर देने के वादा किया है। साथ ही कांग्रेस ने राज्य के 6 समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने का वादा किया है। यही बात अब सत्तासीन भाजपा भी कह रही है। तमिलनाडु में वर्तमान डीएमके सरकार मघालिर उरिमई थोगई योजना के तहत हर माह 1 हजार रू. दे रही है और सत्ता में वापसी पर इसे बढ़ाकर 2 हजार रू. करने का वादा है। ऐसा ही वादा विपक्षी एआईएडीएमके ने भी किया है। साथ में वह महिलाओं को व्यवसाय के लिए 10 हजार रू. एकमुश्त भी देगी।

पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा चुनावी घमासान है, जहां एसआईआर के साथ-साथ सीबीएस (कैश बेनिफिट स्कीम) भी उतनी ही मायने रखती है। ममता दीदी तो अभी प्रति महिला 1500/1700 रू. दे ही रही है, सत्ता की दावेदार भाजपा ने इसे बढ़ाकर 3 हजार करने और सरकारी कर्मचारियों को डीए का बकाया भुगतान करने का वादा भी किया है। जहां देश के अन्य राज्यों में आठवे पे कमीशन की बात हो रही है, वहां पश्चिम बंगाल में अभी भी 6 वेतन आयोग की लागू है।

विस चुनावों में महिलाओं के वोट की कीमत इसी से समझी जा सकती है कि इन पांच राज्यों में कुल 17.4 करोड़ वोटर है, जिनमें से लगभग आधी महिलाएं हैं। तमिलनाडु और केरल में तो महिला वोटरों की संख्या पुरूषों से ज्यादा है। ऐसे में अगर बदलाव की कोई आंधी नहीं चली और नकद रेवड़ी का नुस्खा असर कर गया तो सत्तासीन दलों की सरकार में वापसी ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। यह बात अलग है कि इस तरह नकद पैसा बांटने से सभी सम्बन्धित राज्यों पर सालाना 2 लाख 46 हजार करोड़ रू. का बोझ पर पड़ रहा है। इस घाटे की भरपाई का कोई प्रभावी उपाय उनके पास नहीं है। कुछ राज्य तो कंगाली की तरफ जा रहे हैं। लेकिन सत्ता है तो सब कुछ है, के सिद्धांत के तहत राज्यसत्ता को पाना ही राजनीतिज्ञों के लिए सर्वोपरि है, भले ही इसकी कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े।

भाजपा के 47वें स्थापना दिवस पर मप्र के 17 जिलों में भाजपा कार्यालयों का हुआ भूमिपूजन

सीएम मोहन यादव बोले- धुरंधर-2 का जमाना चल रहा, पाकिस्तान को भी ठिकाने लगाया

भोपाल (नप्र)। सोमवार को भाजपा का 47वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर मध्यप्रदेश के 17 जिलों में कार्यालयों का भूमिपूजन किया गया। भोपाल के प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्राथमिक और सक्रिय सदस्यों का सम्मेलन आयोजित किया गया। यहीं से भूमिपूजन के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल वर्चुअली जुड़े।

इस मौके पर सीएम ने कहा कि भारत तीसरा देश बन गया है, जो अपने दुश्मनों को उनके देश में घुसकर मारता है, जो हमारे अपने देश के अंदर कष्ट देते हैं।

मोदी जी के माध्यम से धुरंधर 2 का समय चल रहा है, लेकिन हमें धुरंधर 1 का समय भी याद आता है। हमें मालूम है कि नकली नोट छाप-छापकर पाकिस्तान परेशान करता था। उस पाकिस्तान को भी क्या ठिकाने लगाया। यह असली धुरंधर का जमाना है।

अपनी परेशानियों का समाधान अपने पास ही है। जब समर्थ और सामर्थ्यशाली नेतृत्व होता है, तो सारे उलझे-सुलझे प्रश्नों का उत्तर मिलता है। तभी तो विक्रमादित्य बनारस में जाकर धर्म की जय-जयकार करते हैं।भोपाल के बीजेपी ऑफिस में सीएम ने पार्टी का ध्वज फहराया।

सीएम बोले- हमने भाजपा को देखा, जिसकी विचारधारा अमर हो गई

सीएम ने कहा- कौन सा फीनिक्स पक्षी है जो राख बनकर फिर जीवित हो जाता है, हमने वह पक्षी नहीं देखा, लेकिन हमने भाजपा को देखा है, जिसकी विचारधारा अटल और अमर हो गई है। हमारे नेताओं का चरित्र और दर्शन अद्भुत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नेतृत्व से भाजपा के हर कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि गठबंधन का दौर लंबे समय तक चला, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार ने अपने वादों को पूरा किया और 24 दलों के साथ सफलतापूर्वक शासन चलाया।

दिवगंत नेताओं के परिजन का हुआ सम्मान

भोपाल में हुए कार्यकर्ता सम्मेलन में सीएम-प्रदेशाध्यक्ष के अलावा क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल समेत में भाजपा के पदाधिकारी, स्थानीय मंत्री, सांसद और विधायक मौजूद रहेइस मौके पर बीजेपी नेताओं ने दिवंगत नेताओं और कार्यकर्ताओं के परिजनों का सम्मान किया। पूर्व विधायक स्वर्गीय रमेश शर्मा के परिजनों का सम्मान करने के दौरान मुख्यमंत्री स्वयं मंच से नीचे उतरकर उनके पास पहुंचे। इसके बाद सीएम, प्रदेशाध्यक्ष का संबोधन हुआ फिर बीजेपी कार्यालयों का भूमिपूजन किया गया। एमपी के 17 जिलों में भाजपा के जिला कार्यालयों के लिए जमीन पहले ही खरीदी जा चुकी थी। अब यहां जिला कार्यालयों का निर्माण कार्य औपचारिक रूप से शुरू हुआ है।

आज से शुरू होगा गांव-बस्ती चलो अभियान

बीजेपी कल यानी 7 से 12 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में गांव-बस्ती चलो अभियान चलाएगी। इस अभियान में सांसद, विधायक, महापौर और नगर पालिका अध्यक्षों से लेकर पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों और नेताओं को भाग लेना होगा।

विधानसभावार 50 गांवों का चयन : पुराने कार्यकर्ताओं के घर पहुंचेंगे नेता

इस अभियान के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 50 बड़े गांवों को चिन्हित कर वहां विशेष कार्यक्रमों की सूची तैयार की गई है। इन गांवों में जाने वाले नेता केवल जनसभाएं ही नहीं करेंगे, बल्कि पार्टी की नींव रखने वाले पुराने और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के घर जाकर उनका आदर-पूर्वक सम्मान भी करेंगे ।

बीजेपी ऑफिस पर सीएम ने फहराया पार्टी का ध्वज

भोपाल के बीजेपी ऑफिस में सीएम मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल ने पार्टी का ध्वज फहराया। कार्यक्रम में बीजेपी के तमाम पदाधिकारी, स्थानीय मंत्री, सांसद, विधायक मौजूद है। यहीं से 17 जिलों के कार्यालय के भूमिपूजन कार्यक्रम में सीएम और प्रदेश अध्यक्ष वर्चुअली जुड़ेंगे।

प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल बोले- 52 जिलों में बीजेपी कार्यालय हो, हमारा लक्ष्य

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि भाजपा की विचारधारा सहभागिता पर आधारित है। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों को दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी और अन्य नेताओं ने आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने अपने मूल विचारों से कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा कि पार्टी 17 जिलों में कार्यालय निर्माण की शुरुआत कर रही है। लक्ष्य है कि अगले स्थापना दिवस से पहले प्रदेश के सभी 52 जिलों में भाजपा के अपने कार्यालय हों। खंडेलवाल ने बताया कि प्रत्येक कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम और पुस्तकालय की व्यवस्था होगी। यहां संगठन और पार्टी विचारधारा से जुड़ी पुस्तकें उपलब्ध रहेंगी।

दो चरण में गेहूं की खरीदी, इस बार केंद्र सरकार की एमएसपी से ज्यादा मिलेगा पैसा

प्रदेश सरकार किसानों को 40 रुपए बोनस देगी

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। रबी सीजन में गेहूं की खरीदी के लिए सरकार ने तारीखों की घोषणा कर दी है। गेहूं की सरकारी खरीदी को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। इस बार प्रदेश में गेहूं की खरीदी दो चरणों में शुरू होगी। पहले चरण में चार संभागों में खरीदी होगी उसके बाद दूसरे चरण में बाकी संभाग में खरीदी की जाएगी।

कौन से संभाग में कब से खरीदी- 9 अप्रैल 2026 से इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभागों में गेहूं की खरीदी की जाएगी। इसके अलावा 15 अप्रैल से प्रदेश के बचे हुए संभाग ने गेहूं की खरीदी शुरू की जाएगी। 15 अप्रैल से ग्वालियर, चंबल, जबलपुर, रीवा, सागर और शहडोल संभाग में गेहूं खरीदी के सेंटर खोले जाएंगे।

7 तारीख से बुक होंगे स्लॉट- पहले फेज की गेहूं खरीदी के लिए 7 अप्रैल से स्लॉट बुक किए जाएंगे। किसान ऑनलाइन माध्यम से अपनी पसंद की मंडी और तारीख सिलेक्ट कर अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। स्लॉट बुक होने के बाद किसान के पास अपनी उपज बेचने के लिए एक सप्ताह का समय रहेगा।

कितने किसानों ने कराया है रजिस्ट्रेशन- गेहूं खरीदी के पंजीयन करने के लिए सरकार ने पहले की पोर्टल खोल दिए थे। इस बार प्रदेश के करीब 19 लाख से ज्यादा किसानों ने एमएसपी पर गेहूं बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। वहीं, प्रशासन ने खरीदी केंद्रों पर बारदाने, छांव और पानी जैसी बेसिक सुविधाओं को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। इस बार पेमेंट सिस्टम को भी फास्ट बनाया गया है।

किसानों को मिलेगा बोनस- मध्य प्रदेश सरकार ने इस बार किसानों को बोनस देने का फैसला किया है। केंद्र सरकार द्वारा तय की गई एमएसपी के ऊपर बार राज्य के किसानों को 40 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के किसानों को इस बार सरकारी दाम पर गेहूं बेचने पर 2625 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा।

दो चरणों में खरीदी का फैसला क्यों

- जिन संभागों में गेहूं की फसल की जल्दी आवक होती हैं वहां जल्दी खरीदी होगी
- उपज के जल्दी आवक वाले इलाकों में पहले खरीदी शुरू करने का फैसला किया गया
- दो-फेज में खरीदी करने से लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन मैनेज करने में आसानी होगी
- किसानों को गेहूं खरीदी के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा
- किसी भी सेंटर पर अचानक भीड़ बढ़ने से रोकने के लिए

नाले में तैरती मिली 22 पेटी शराब की बोतलें

मुरैना में तेज बारिश के बाद खुला राज, लूटने के लिए पहुंच गए थे ग्रामीण

मुरैना (नप्र)। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में अजीब मामला सामने आया है। यहां पर नाले में शराब की बोतलें तैरती हुई दिखाई दी हैं। एक या दो बोतल नहीं बल्कि 1000 से ज्यादा बोतलें नाले में तैर रही थीं। जिसे लूटने के लिए गांव वालों की भीड़ जमा हो गई। कई लोगों ने तो शराब की कई बोतलें लूटीं हालांकि कुछ लोगों ने इसे जहरीले शराब बताते हुए लूटने वालों को रोका। यह पूरा घटनाक्रम मुरैना के कैलारस थाना इलाके में स्थित सेमई का है। दरअसल, सेमई से एक नाला होकर गुजरता है। सेमई चौराहे पर इस नाले पर पुलिया भी बनी हुई है। शनिवार को यहां तेज बारिश हुई थी उसके कुछ देर बाद इस नाले में शराब की बोतलें तैरती हुई दिखाई देने लगीं। बड़ी संख्या में शराब की बोतल पानी में तैरती हुई देख ग्रामीण भी हैरान रह गए। इसकी जानकारी तुरंत पुलिस प्रशासन को दी गई।

1000 से ज्यादा बोतलें जब्त- मौके पर पुलिस पहुंची और नाले में तैरती हुई 1000 से ज्यादा शराब की छोटी बोतलों को जब्त किया। पुलिस के अनुसार, नाले की पुलिया के नीचे अवैध शराब का कारोबार करने वाले माफिया ने बोतलें छुपा कर रखी होगी। जब बारिश हुई और नाले की पुलिया के नीचे पानी का स्तर बढ़ा तो यह शराब की बोतलें पानी की सतह पर दिखने लगी। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। लेकिन ग्रामीण इस बात से हैरान है कि आखिर पुलिया के नीचे इतनी बड़ी मात्रा में शराब की बोतल है कहां से आईं।

ग्रामीणों के अनुसार यह नकली या जहरीली शराब हो सकती है। इसे रात के अंधेरे में नाले में फेंका गया है। हालांकि कैलारस टीआई ने नकली या जहरीली शराब की संभावनाओं से इंकार किया है। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि शराब की बोतलों पर आबकारी विभाग दर्ज है और शराब निर्माण 2025 में हुआ है।

कलेक्टर साहब का 'रील' प्रेम

विंध्य के एक नवागत कलेक्टर साहब इन दिनों 'मंत्रालय' से लेकर 'मेटा' (फेसबुक-इंस्टाग्राम) तक छाए हुए हैं। साहब जनसुनवाई में ऐसे घुल-मिल रहे हैं कि जनता को उनमें अपना 'मसीहा' और नेताओं को अपना 'प्रतिद्वंद्वी' नज़र आने लगा है। पुराने जिले में भी साहब अपनी इसी कार्यशैली और कैमरामैन के लिए मशहूर थे। अब नए जिले में विंध्य की भोली जनता तो वाह-वाही कर रही है, लेकिन क्षेत्र के माननीयों का रक्तचाप बढ़ गया है। डर यह है कि अगर कलेक्टर साहब ही सारे 'लाइक' और 'फॉलोअर्स' बटोर लेंगे, तो फिर चुनाव में नेताओं के हिस्से क्या सिर्फ़ 'ब्लॉक' होना बचेगा?

मोहन का मंत्रालय
आशीष चौधरी

फाइल की 'बुलेट ट्रेन'

मंत्रालय में वैसे तो रिटायरमेंट के बाद संविदा की फाइल कछुए की रफ्तार से चलती है, लेकिन कुछ 'खास' लोगों के लिए नियम-कायदे भी ट्रैक बदल लेते हैं। पिछले दिनों एक डिप्टी सेक्रेटरी साहब रिटायर हुए। अभी विदाई की मिठाई भी नहीं बंटी थी कि 'चौथी मंजिल' से फोन आ गया–'आप कहीं नहीं जा रहे!' फिर क्या था, संविदा नियुक्ति की फाइल पर ऐसे पंख लगे कि वह मंत्रालय के इतिहास की सबसे तेज दौड़ने वाली फाइल बन गई। कैबिनेट की मंजूरी ऐसी मिली जैसे कोई इमरजेंसी रेस्क्यू ऑपरेशन हो। इसे कहते हैं योग्यता की कद्र.. !

संगठन में 'संग्राम'

प्रदेश के कर्मचारी संगठन में वर्चस्व की जंग अब पुलिस थाने की देहलीज़ तक जा पहुंची है। सामान्य प्रशासन विभाग ने एक गुट को मान्यता क्या दी, दूसरे गुट वाले आईएएस साहब के 'लीडरशिप' पर ही सवाल खड़े हो गए। एक गुट को सत्ता का वरदहस्त प्राप्त है, ताकि 'क्षेत्र विशेष' के नेताजी को खुश रखा जा सके। वहीं दूसरे गुट के मुखिया अपने 'बड़बोलेपन' के कारण सरकार की गुड-बुक्स से बाहर हैं। वैसे चर्चा है कि सरकार ने दूसरे गुट को हाशिये पर लाकर संगठन में मजबूत पकड़ को कमजोर करने का प्रयास किया है क्योंकि दूसरा गुट ज्यादा प्रभावशाली था। अब मंत्रालय की सीढ़ियों पर यह भी चर्चा है कि ये संगठन कर्मचारियों का भला करेंगे या आपस में ही 'कुश्ती' लड़कर मनोरंजन?

सूचना आयोग : तीसरा कौन?

राज्य सूचना आयोग में तीन पदों के लिए विज्ञापन निकला था, लेकिन 'सिलेक्ट' सिर्फ दो ही हुए। दोनों नवनियुक्त आयुक्तों ने मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी हाजिरी बजा दी है और शपथ की तैयारी है। पर सवाल वही है–'वो तीसरा कौन?' गलियारों में चर्चा है कि तीसरी कुर्सी किसी बहुत ही 'खास' चेहरे के लिए खाली रखी गई है, जिसकी एंट्री सही मुहूर्त पर होगी। आखिर सस्पेंस बना रहना भी तो राजनीति का हिस्सा है!

मंत्रीजी का 'प्रोजेक्ट' पास, डॉक्टर 'फेल'

कहते हैं 'दीया तले अंधेरा' होता है, लेकिन यहाँ तो दीया ही बुझा हुआ है। प्रदेश के एक रसूखदार मंत्रीजी के गृह क्षेत्र में उनके 'ड्रीम प्रोजेक्ट' ने तो आकार ले लिया, लेकिन वहां की जनता एक अदद डॉक्टर के लिए तरस रही है। विडंबना देखिए, मंत्रीजी खुद विभाग के मुखिया हैं, पर उनके आश्वासन 'हवाई' साबित हो रहे हैं। जब गृह क्षेत्र का ये हाल है, तो प्रदेश के बाकी स्वास्थ्य केंद्रों का भगवान ही मालिक है। मंत्रीजी, प्रोजेक्ट्स की चमक अच्छी है, पर जनता की धड़कनें भी तो सुनिए!

चाय की चुस्की और पाला बदलने की 'खुशबू'

पिछले दिनों मंत्रालय की पांचवीं मंजिल पर एक ताकतवर अफसर और कांग्रेस के दो 'हाशिए' वाले दिग्गजों के बीच लंबी गुफ्तगू हुई। बंद कमरे में चाय की चुस्कियां ली गईं और माहौल इतना हल्का था कि बाहर खड़े सुरक्षाकर्मियों को भी 'महक' आ गई। एक नेताजी या कहें कि विधायक जी अपनी जिम्मेदारी से इस्तीफा दे चुके हैं, दूसरे पूर्व विधायक को संगठन भाव नहीं दे रहा। अब इस 'गुपचुप' मुलाकात के बाद अटकलें तेज हैं कि क्या विपक्ष का ये 'कद्दावर' हाथ अब 'कमल' थामने की तैयारी में है? क्योंकि साहब, राजनीति में मुलाकातें बेवजह नहीं होतीं और राज्यसभा के लिए सत्ताधारी भाजपा आंकड़े बढ़ाने में लगी है !